

मत पत्र में क्रं.



बी.एस.एन.एल. एम्प्लाइज यूनियन

मध्यप्रदेश परिमंडल का मुख्यपत्र

Regd. No. 4896

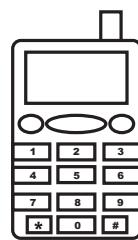
9

BSNLEU

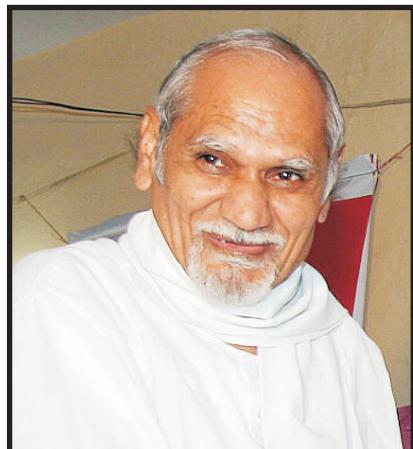
संचार लोक

संपादक : प्रकाश शर्मा, परिमंडल सचिव

मोबाईल पर



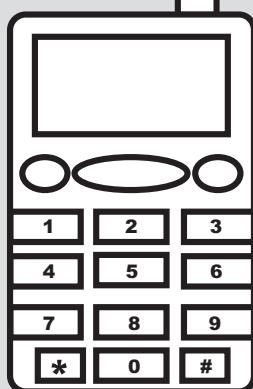
मोहर लगाएँ



हमारे प्रेरणा स्रोत

बी.एस.एन.एल. एम्प्लाइज यूनियन

के चुनाव चिन्ह □ मोबाईल पर



मतपत्र के क्र. 9 पर मोहर लगाकर भारी बहुमत से विजयी बनाइये

मतदान दिनांक - 10 मई 2016



बी.एस.एन.एल. एम्प्लाइज यूनियन

मध्यप्रदेश परिमंडल, भोपाल

↗ दिल की कलम से.... मन की बात

प्रिय साथियों

विशाखा पट्टनम में 22 मार्च 2001 में हुई स्थापना पश्चात् संघर्षों और सफलताओं की चैम्पियन यूनियन बीएसएनएलईयू अपने 15 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। 15 वर्षों के इस सफर में बीएसएनएलईयू ने न केवल पीएसयूज की ट्रेड यूनियन्स् में अपना एक विशिष्टस्थान बनाया है वरन् वर्किंग क्लास के विरोध में सरकार की मजदूर-कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने में भी वह अग्रणी और काफी हद तक सफल भी रही है।

मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं उस यूनियन का परिमंडल सचिव के रूप में मध्यप्रदेश में अपनी सशक्त टीम के साथ नेतृत्व करता हूं जिसने बहुत ही अल्प समय में, बीएसएनएल की विपरीत वित्तीय स्थितियों में उच्चतम वेतनमान अपने कर्मियों के लिए हासिल किया और श्रेष्ठतम प्रमोशन पॉलिसी के लिए भी प्रबंधन को बाध्य किया, संयुक्त संघर्ष की अवधारणा के तहत सभी यूनियन्स् एसोसिएशन्स् को एक बेनर तले लाकर बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन ने बीएसएनएल की जीवंतता हेतु कई संघर्ष भी किए।

परिणामस्वरूप “एक छूटते जहाज” की संज्ञा से जिस बीएसएनएल को आहत किया जा रहा था वह बीएसएनएल आज लाभ की स्थिति की ओर अग्रसर है। हमने बीएसएनएल को विगत वित्तीय वर्ष के रु.691 करोड़ के “ऑपरेशनल लॉस” की स्थिति से इस वित्तीय वर्ष में रु.672 करोड़ के “ऑपरेशनल प्रॉफिट” की स्थिति में ला खड़ा किया है। कभी “डिलाइट मंथ” तो कभी “मुस्कान के साथ सेवा” जैसी योजनाओं के साथ प्रबंधन और हम सभी ने मिलकर बीएसएनएल के राजस्व में वृद्धि की ओर भी कदम बढ़ाया है और एक नई कार्य संस्कृति का उदय हम बीएसएनएल में देख रहे हैं जहां परिमंडलों के मुखिया (सीजीएम) भी रैलियों में विभिन्न योजनाओं के लिए सङ्घक पर उत्तर कर्मियों का नेतृत्व कर रहे हैं। करने के लिए बाध्य हुए हैं। और तो और बीएसएनएल कर्मियों के प्रयासों से अभिभूत हमारे माननीय मंत्री महोदय ने भी अभी हाल ही में यह बयान दिया है कि बीएसएनएल के आर्थिक उन्नयन के लिए वे भी सिम बेचने को तैयार हैं। बीएसएनएल को जिंदा रखने की यह जिद और जुनून हर शख्स में पैदा करने में बीएसएनएलईयू की नेतृत्वकारी भूमिका है।

साथियों, बीएसएनएल के आर्थिक उन्नयन और कर्मचारियों के भविष्य की सामाजिक-व्यक्तिगत और आर्थिक स्तर पर सुदृढ़ता के लिए बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन के प्रयासों और संघर्षों से आप वाकिफ हैं।

विनिवेश, निजीकरण, अनबंडलिंग, बीएसएनएल-एमटीएनएल मर्जर, टॉवर कंपनी, व्ही आर एस, डेलॉईटी कंसलटेंट की अनुशंसाओं का पूर्णरूपेण विरोध कर सभी के भविष्य को सुरक्षित-सुदृढ़ बनाए रखने में बीएसएनएलईयू सफल हुई है। बीएसएनएलईयू की ग्यारह वर्षों में हासिल कामयाबी की फेरहिस्त अन्य यूनियनों के वर्षों के कार्यकाल सूची से कहीं अधिक लंबी है। इसीलिए हमारी प्रतिस्पर्धी यूनियन के निरर्थक आरोपों से हम किंचित रूप से भी विचलित नहीं हैं। हमारी कोशिश है कि हम हमारी उपलब्धियों पर ज्यादा फोकस करें। 10.5.2016 को केवल यूनियन की मान्यता के लिए होने वाले रूटीन चुनाव मात्र नहीं है... वरन् एक जंग है... बीएसएनएल को बचाने और बीएसएनएल को बेचने वालों के बीच और इस जंग में आपकी भूमिका निर्णयक है। 2004 से लगातार आप और हम आपसी विश्वास के खुबसूरत बंधन में बंधे हैं और परस्पर विश्वास का यह रिश्ता 10.5.2016 को निःसंदेह और ज्यादा प्रगाढ़ होगा... विश्वास है हमें।

आईए, 10.5.2016 को आप और हम बीएसएनएल की नींव को, हमारे भविष्य की जड़ों को और अधिक सशक्त बनाएं... एक सही और सूझबूझ भरे निर्णय के साथ... क्र. 9 के समक्ष मोबाईल पर मोहर लगाकर।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ...

आपका ही
प्रकाश शर्मा,
परिमंडल सचिव
(अपनी पूरी टीम के साथ)

सोचिए, समझिए, मंथन कीजिए और फिर निर्णय लीजिए सवाल बीएसएनएल के अस्तित्व का है, हमारे भविष्य का है

1.1.2017 से हमें बेहतरीन वेतनमान चाहिए और बेहतरीन वेतनमान प्राप्ति के लिए सिर्फ एक सशक्त यूनियन चाहिए

यूनियन की मान्यता के चुनाव 10 मई 2016 को होंगे। ये चुनाव, यूनियन/ यूनियनों की मान्यता के लिए 2013 के नियमों के अनुसार होने वाले हैं। नियम बीएसएनएल के द्वारा बनाये गये हैं। यूनियन की मान्यता के लिए पिछले 5 चुनाव, कोड ऑफ डिसिप्लीन के प्रावधानों के अनुसार हुए थे जिसमें सिर्फ एक ही यूनियन को मान्यता देने का प्रावधान था। किन्तु नए नियमों के अनुसार, एक से अधिक यूनियन को मान्यता देने का प्रावधान है। नये नियमों के अनुसार 35% प्रतिशत या अधिक मत प्राप्त करने वाली यूनियन को प्रथम यूनियन के रूप में मान्यता दी जावेगी जबकि 15% या अधिक मत प्राप्त करने वाली यूनियन को दूसरे नम्बर की यूनियन के रूप में मान्यता मिलेगी। किन्तु, यदि किसी यूनियन को 50% या अधिक मत प्राप्त होते हैं तो, ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही यूनियन को मान्यता प्राप्त होगी। एक ही यूनियन को मान्यता प्राप्त होने की स्थिति में भी, नेशनल काउन्सिल, सर्किल काउन्सिल तथा लोकल काउन्सिल में यूनियन/ यूनियनों को प्राप्त होने वाले मतों के अनुपात में स्टाफ पक्ष में प्रतिनिधियों की नामजदगी होगी। 7% से अधिक किन्तु 15% से कम मत प्राप्त करने वाली यूनियन का भी एक प्रतिनिधि काउन्सिलों में नामजद किया जावेगा। प्रथम दर्जे की यूनियन का प्रतिनिधि काउन्सिलों में सचिव होगा जबकि दूसरे दर्जे की यूनियन का प्रतिनिधि लीडर होगा। मतों का प्रतिशत, चुनाव में पड़ने वाले वोटों के आधार पर नहीं निकाला जावेगा बल्कि मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं (कर्मचारियों) की संख्या के आधार पर निकाला जावेगा। मान्यता के लिए नियमों के अनुसार प्रथम दर्जे की यूनियन तथा दूसरे दर्जे की यूनियन को समझौता करने/ एग्रीमेंट पर सहमति बनाने आदि मुद्दों पर बराबरी का दर्जा प्राप्त रहेगा।

यह बात ध्यान में रखकर ही 10 मई 2016 को होने वाले चुनाव में मतदान करना होगा कि, बीते हुए समय में किस (किन यूनियनों) यूनियन का ट्रेक रिकार्ड किस प्रकार का रहा है। इस बात को ध्यान में रखकर भी मतदान करना होगा कि, एन एफ टी ई ने सितम्बर 2000 में संचार विभाग को कम्पनी में बदलने के एग्रीमेंट करते समय एन एफ टी ई ने एग्रीमेंट में इस

बात का कोई उल्लेख नहीं करवाया था कि, सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कन्सालीडेटेड फंड से पेंशन मिलेगी, कर्मचारियों की सेवा शर्तें क्या होंगी, कर्मचारियों के पदोन्तति के अवसर क्या होंगे, कम्पनी को बेचा जावेगा या नहीं? तथा कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी या नहीं? इसके विपरीत, एनएफटीई ने एग्रीमेंट में यह धारा जुड़वाई थी कि, कम्पनी बनने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 (एन) के प्रावधान लागू होंगे जिसके अनुसार यदि किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालना होगा तो उसे तीन माह का नोटिस दिया जावेगा या एक माह का एडवांस वेतन देकर तुरन्त ही नौकरी से निकाल दिया जावेगा।

उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत, बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन का शानदार ट्रेक रिकार्ड है। दिसम्बर 2004 में मान्यता मिलने के बाद बी एस एन एल एम्प्लाइज यूनियन ने जनवरी 2005 में ही यह आदेश निकलवाया था कि वही आर एस की योजना वापिस ली जाती है तथा मार्च 2005 में यह आदेश जारी करवाया कि सेवा निवृत्त होने पर कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कन्सालीडेकटेड फंड (ट्रस्ट बनाकर नहीं) से पेंशन दी जावेगी। इसके अतिरिक्त, अपनी मान्यता की 11 साल की समयावधि में, बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन ने सभी एक्जीक्यूटिव और नान एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों को एक मंच पर लाने के लिए ज्वाइंट फोरम, ज्वाइंट एक्शन कमेटी तथा फोरम आदि का गठन करके, बीएसएनएल की पूरी बिरादरी की एकता कायम की। इसी एकता के आधार पर बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन के नेतृत्व में संघर्षों की पूरी श्रृंखला बनाई गई तथा शानदार हड्डतालें हुई। इन्हीं संघर्षों और हड्डतालों का ही परिणाम है कि आज तक बी एस एन एल का एक भी शेयर नहीं बेचा जा सका है तथा बी एस एन एल सरकारी क्षेत्र की कम्पनी बनी हुई है। इनके अतिरिक्त शानदार वेतन समझौता किया गया तथा ऐतिहासिक 5 प्रमोशन की पालिसी बनवाई गई। कर्मचारी को छंटनी से बचाया गया।

अनुरोध : संचारलोक के इस चुनाव विशेषांक में हमने कुछ कड़वी तो कुछ सधी, अच्छी और मीठी सद्याइयों को आपसे लबरु कराने की कोशिश की है। समय निकाल कर पढ़िएगा जरूर... 10.5.2016 को आपके लिए निर्णय लेना आसान होगा... सहज होगा...

केन्द्र सरकार की बीएसएनएल विरोधी नीतियों के कारण बीएसएनएल को घाटे की कम्पनी बना दिया गया है। 01.01.2017 से बीएसएनएल के कर्मचारियों का वेतन रिवीजन होना है। उल्लेखनीय है कि मीडिया की खबरों के अनुसार बीएसएनएल के सीएमडी श्री अनुपम श्रीवास्तव जी का बयान है कि बीएसएनएल के घाटे की स्थिति में वेतन रिवीजन नहीं किया जायेगा, इस पर बीएसएनएल ई.यू. की कड़ी प्रतिक्रिया है कि घाटे के लिए केन्द्र सरकार एवं बीएसएनएल प्रबंधन की नीतियां जिम्मेदार हैं इसलिए सरकार और प्रबंधन की गलती की सजा कर्मचारियों को क्यों? ऐसे वक्त में एनएफटीई मौन रहती है। किन्तु दुष्प्रचार, आरोप-प्रत्यारोप, दोषारोपण में सदैव अग्रणी रहना और संघर्ष के वक्त पीठ में छूरा भौंकने में एनएफटीई अग्रणी रही है। इसके अलावा बीएसएनएल में पूंजीपतियों की गिर्द दृष्टि बनी हुई है। पूंजीपति बीएसएनएल को हड्डप लेना चाहते हैं और सरकार भी बीएसएनएल को घाटे में लाकर बेच देने के नाकाम मसूबे बनाये हुए हैं। अभी तक हमने बीएसएनएल को बचाया है। लेकिन आगे संकट बहुत ही गहरा है एक ओर पूर्ण बहुमत की केन्द्र सरकार जो लगातार पूंजीपतियों के पक्ष में नीतियां बना रही है वहीं दूसरी तरफ 1.1.2017 से वेतन रिवीजन प्राप्त करने की भी चुनौती हमारे सामने हैं। अगला वेतनमान फिर 2027 में ही मिलेगा। इसलिए आज एक सशक्त, मजबूत एवं एक ही यूनियन के एक मात्र मान्यता में होने की आवश्यकता है। यदि पिछले चुनाव के परिणाम देंखें तो बीएसएनएलईयू को 48.6% वोट प्राप्त हुए थे जो कि मुख्य मान्यता प्राप्त यूनियन बनी थी,

जबकि एनएफटीई को मात्र 30.28% वोट प्राप्त हुये थे जो कि दूसरे दर्जे की मान्यता प्राप्त यूनियन बनी थी एवं तीसरे नम्बर पर एफएनटीओ थी जिसे 6.89% वोट हासिल हुए थे। पिछले चुनाव के परिणाम के अनुसार बीएसएनएलईयू एकमात्र मान्यता प्राप्त 1.4% वोट की कमी से सोल यूनियन बनने से रह गई थी। वर्तमान में यूनियनों की सदस्यता के आंकड़ों को देखें तो 65% सदस्यता बीएसएनएलईयू के पास है जिससे स्पष्ट है कि इस बार बीएसएनएलईयू का सोल यूनियन बनना लगभग तय है। लेकिन किसी भी प्रकार की चूक न हो इसलिए हर कर्मचारी चाहे वह एनएफटीई का सदस्य ही क्यों न हो तक अपनी बात पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यूनियन की मान्यता के फैसले के साथ साथ हमारे भविष्य का भी फैसला होने जा रहा है। जिस तरह यूनियनों को काउन्सिलों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व देने के लिए बीएसएनएलईयू द्वारा मान्यता के नये नियम बनवाना समय की पुकार थी ठीक उसी प्रकार 50% से अधिक मत प्राप्त करके सिर्फ बीएसएनएलईयू को सोल यूनियन (सिर्फ एक यूनियन) बनाना समय की पुकार है। चूंकि एनएफटीई का ट्रेक रिकार्ड सरकार समर्थक और कर्मचारी विरोधी है, एनएफटीई ने ही विभाग को कम्पनी बनवाया है इसलिए एनएफटीई को मान्यता मिलने से रोका जाना चाहिए, इसलिए अपना और बीएसएनएल का भविष्य सुरक्षित और सुदृढ़ कीजिए। अपील करते हैं कि बीएसएनएलईयू को 50% से अधिक मतों से जीत दिलाकर बीएसएनएलईयू को एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन बनाईये।

वक्त दो टूक फैसले का है... बीएसएनएल की जीवंतता का है... हमारे भविष्य का है ...

प्रिय साथियों

10.5.2016 – एक ऐसा दिन जब निर्धारण होगा
बीएसएनएल के और हमारे भविष्य का। इसी दिन यह तय होगा कि बीएसएनएल को जिंदा रखने की कोशिशें और अधिक पुरुष्टा होगी या बीएसएनएल की जीवंतता के प्रयास आहत होंगे। इसी दिन शायद यह भी तय हो जाएगा कि 1.1.2017 से होने वाले वेतन पुनरीक्षण में हम कर्मचारियों के हितार्थ कितनी सक्षमता से “बारगेन” कर पाएंगे।

10.5.2016 को होने वाला वेरिफिकेशन एक बेहद महत्वपूर्ण वेरिफिकेशन के रूप में जाना जाएगा। हम आपसे बीएसएनएलईयू के पक्ष में क्र.9 के समक्ष मोबाइल चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा कर बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन को एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन बनाने के अनुरोध के

साथ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर गौर करने का अनुरोध भी जरूर करेंगे।

साथियों आपकी स्मृतियों में शायद एनएफटीई के नेतृत्व में बीएसएनएल और हम सभी कर्मियों के साथ जो छल हुआ है उसकी यादें अभी भी ताजा होंगी। निःसंदेह आपकी स्मृतियां कभी कभी या जब कभी आपके म स्तिष्ठक में मूर्त रूप लेती होंगी तो आप विचलित होते होंगे। किन्तु साथ ही आपकी उसी मनःस्थिति के दौरान बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन द्वारा बीएसएनएल और आपके भविष्य की सुदृढता के लिए किए गए प्रयास पर दृष्टिपात करने पर आप राहत भी महसूस करते होंगे.....हमें विश्वास है।

“आहत और राहत” से भरे कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमने आपके चिंतन के लिए इस अंक में प्रस्तुत करने की कोशिश की है।

सरकार से सांठगांठ कर बीएसएनएल बनाने में सहयोगी एवं कर्मचारी विरोधी नीतियों की पक्षधर एनएफटीई पर इस बार प्रहार जरूरी है

★ बीएसएनएल बनाने में एनएफटीई शामिल

यदि पब्लिक सेक्टर कम्पनियों को बर्बाद कर दिया जावेगा तो इससे मल्टीनेशनल कम्पनियों और बड़े औद्योगिक घरानों को देश की सम्पत्ति को लूटना बहुत आसान हो जावेगा। इसी सच्चाई को ध्यान में रखकर हमने संचार विभाग को कम्पनी में बदलने की सरकारी योजना का विरोध किया था। इसलिए सन 2000 में आल इंडिया टेलीकाम एम्प्लाइज यूनियन क्लास 3 (नम्बूदरी), आल इंडिया टेलीग्राफ ट्रेफिक एम्प्लाइज यूनियन क्लास-3 तथा आल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लाइज यूनियन क्लास-3 एवं क्लास 4 सहित 6 यूनियनों ने संचार विभाग को कम्पनी में बदलने के विरोध में धरना—प्रदर्शनों की एक पूरी श्रखला बनाई थी। इसके साथ ही इन 6 यूनियनों ने नेशनल एकशन कमेटी (एनएसी) बनाकर कम्पनी न बनाने के विरोध में 28 जून 2000 को एक दिन की शानदार हड्डताल की थी किन्तु फिर भी जब उस समय की एन डी ए सरकार कम्पनी बनाने की योजना पर आमादा दिखी तो 6 यूनियनों की एनएसी ने 24 और 25 अगस्त 2000 को विरोध किया था। ध्यान देने की बात है कि एनएफटीई इस हड्डताल में शामिल नहीं हुई थी और कम्पनी बनाने के लिए सरकार का साथ दिया था और तीन दिवसीय हड्डताल के दौरान भी ऐन वक्त पर हड्डताल वापस लेकर विश्वासघात किया और बीएसएल बना।

★ बीएसएनएल बनने से रोका जा सकता था

नेशनल एकशन कमेटी द्वारा आहुत 24–25 अगस्त 2000 की हड्डताल में संचार विभाग के 2 लाख से अधिक कर्मचारियों ने हड्डताल में शामिल होकर कम्पनी बनाने का विरोध किया था। कम्पनी बनाने के कर्मचारी विरोधी मूड का उपयोग करके उस समय की मान्यता प्राप्त यूनियन एनएफटीई सरकार पर दबाव पैदा करके संचार विभाग को कम्पनी में बदलने से रोक सकती थी। किन्तु एनएफटीई ने सरकार का साथ दिया और कम्पनी बनाने का स्वागत किया। इससे सरकार के लिए संचार विभाग को बीएसएनएल में बदलना आसान हो गया।

★ एनएफटीई ने दहशत और प्रलोभन दोनों का

उपयोग किया

जिस समय बाजपेही की एन डी ए सरकार संचार विभाग को कम्पनी में बदलने की अपनी योजना पर जोर शोर से काम कर रही थी, उस समय एन एफ टी ई भी कर्मचारियों के कम्पनी विरोधी मूड को धीमा करने के लिए लगातार यह प्रचार कर रही थी कि कम्पनी बन जाने की स्थिति में कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भारी वृद्धि होगी। इसलिए कम्पनी को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। एनएफटीई ने यह भी कुत्सित प्रचार किया था कि जो कर्मचारी कम्पनी में नहीं जावेंगे उन्हें सरप्लस सेल में भेज दिया जावेगा तथा उनकी छंटनी हो जावेगी। इस प्रकार से एनएफटीई ने कम्पनी बनाने में सरकार का साथ देने के लिए प्रलोभन और दहशत, दोनों ही हथियारों का उपयोग किया था।

★ बीएसएनएल बनने की योजना के के विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट गए :—

संचार विभाग को कम्पनी बनाकर बेच देने की सरकारी योजना को राष्ट्रीय हितों के विपरीत होने की दलील के साथ हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर की थी। किन्तु मान्यता प्राप्त संघ एनएफटीई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया था कि संचार विभाग के कर्मचारी कम्पनी बनाने के विरोध में नहीं है। अतः हमारी रिट याचिका खारिज हो गई थी।

★ एन.एफ.टी.ई. ने व्ही.आर.एस. देने का समझौता कर कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया

यह गैर विवादित सच्चाई है कि जब 2002 से 2004 के बीच एनएफटीई को मान्यता थी कि तो उसने कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए कर्मचारियों को व्ही.आर.एस. देने के लिए मैनेजमेंट को हरी झंडी दी थी। दिनांक 24.03.2004 को सम्पन्न नेशनल काउन्सिल की मीटिंग के मिनिट्स जारी करते हुए मैनेजमेंट ने लिखा था कि एनएफटीई (बीएसएनएल) की सहमति से व्हीआरएस की योजना तैयार की गई है। मैनेजमेंट ने, यद्यपि यह भी लिखा था कि व्ही.आर.एस. की यह योजना स्वैच्छिक होगी किन्तु अपने अंतिम स्वरूप में यह योजना सीआरएस (जबरन सेवा निवृत्ति) में

बदल जाती।

किन्तु दिसम्बर 2004 में, बी एस एन एल एम्प्लाइज यूनियन को मान्यता मिलने के बाद दिनांक 25.01.2005 को सम्पन्न नेशनल काउन्सिल की मीटिंग में बीएसएनएल ई.यू.एवं यूनाईटेड फोरम के दबाव के कारण मैनेजमेंट को व्ही.आर.एस. की योजना वापिस लेने की घोषणा करना पड़ी थी।

★ एन.एफ.टी.ई. का सन् 2002 में कर्मचारियों के साथ में छल

बीएसएनएल बनने के बाद यूनियन की मान्यता के लिए प्रथम चुनाव सितम्बर 2002 में सम्पन्न हुआ था। इस चुनाव के सम्पन्न होने के पूर्व बीएसएनएल की सभी यूनियनों ने सीडीए (केन्द्रीय वेतनमान) से आईडीए (औद्योगिक वेतनमान) में जाने के लिए बीएसएनएल के मैनेजमेंट के साथ संयुक्त रूप से चर्चा की थी। इसके लिए सभी यूनियनों ने गंभीर विचार-विमर्श करने तथा अन्य कम्पनियों के कर्मचारियों को मिल रहे वेतन के आधार पर रु. 4400/- न्यूनतम वेतन (आर.एम.के लिए) की मांग की थी। इस मांग पर मैनेजमेंट के साथ दो राउन्ड की चर्चा भी हो गई थी। किन्तु इसी बीच एनएफटीई ने पीछे के दरवाजे से प्रवेश कर रु. 4400/- के स्थान पर 1000/- रु. कम करके रु. 3400/- न्यूनतम वेतन की मांग प्रस्तुत कर दी। इसलिए एनएफटीई की इस धोखाधड़ी के कारण रु 4400/- न्यूनतम वेतन नहीं मिल सका। फिर भी सभी यूनियनों और विशेष रूप से बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन के दबाव के कारण रु. 4000/- न्यूनतम वेतन प्राप्त किया गया था।

★ एनएफटीई ने दो अलग-अलग वेतन मानों की मांग की थी:-

एनएफटीई ने यह मांग की थी कि, कम्पनी बनने के बाद कर्मचारियों के लिए दो वेतनमान बनाये जावें, पहिला तो केन्द्रीय वेतनमान हो, जिसके आधार पर सेवा निवृत्त होने

के बाद पेंशन दी जावे तथा दूसरा औद्योगिक वेतनमान हो जिसके आधार पर सेवाकाल में वेतन दिया जावे। किन्तु बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन के नेतृत्व में यूनाईटेड फोरम के सख्त विरोध के कारण मैनेजमेंट को सिर्फ औद्योगिक वेतनमान ही बनाना पड़ा। यह ध्यान देने की बात है कि यदि एनएफटीई का दो वेतनमान वाला प्रस्ताव मान लिया गया होता तो इस समय प्रत्येक कर्मचारी को रु. 3000/- से लेकर रु. 4000/- तक कम पेंशन मिलती।

★ नये वेतन समझौते में एनएफटीई की अडंगेबाजी

नया वेतन समझौता करने के लिए बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन एवं यूनाईटेड फोरम ने एनएफटीई को समझौतावार्ता में शामिल होने के लिए अनेकों बार आग्रह किया था। किन्तु समझौतावार्ता में वे शामिल नहीं हुए, अलबत्ता यह शर्त लगायी कि, वेतन समझौते पर हस्ताक्षर करने की शर्त पर हम वेतन वार्ता में शामिल होंगे। उनकी यह शर्त नहीं मानी जा सकती थी क्योंकि गैर मान्यता प्राप्त यूनियन के हस्ताक्षर वाला समझौता अवैध होता है। इस प्रकार एनएफटीई ने नया वेतन समझौता सम्पन्न होने में भी अडंगेबाजी की।

वेतन समझौता करने में मैनेजमेंट द्वारा विलम्ब किया जा रहा था। तब शीघ्र ही वेतन समझौता करने की मांग को लेकर बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन के नेतृत्व में यूनाईटेड फोरम ने अनेकों संघर्ष किये तथा 19–20 अगस्त 2009 को दो दिवसीय हड़ताल की तो एनएफटीई द्वारा संघर्षों और हड़ताल में शामिल होने की बजाय, आदतन अपने चरित्र के अनुरूप मैनेजमेंट का ही साथ दिया। एनएफटीई ने ही मैनेजमेंट से कहा कि वह मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ समझौता न करें तथा एकतरफा नये वेतनमानों की घोषणा कर दे। किन्तु 19–20 अगस्त 2009 को दो दिवसीय हड़ताल की जबर्दस्त कामयाबी के कारण मैनेजमेंट को बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन के साथ समझौता करना पड़ा।

डर से मत डरोडर के आगे जीत है....

वर्तमान में 55 से 59 वर्ष की आयुवर्ग के साथियों का डाटा प्रबंधन द्वारा मांगा गया है। इस मुद्रदे को एनएफटीई चुनाव के मद्देनजर अपने चरित्र के अनुरूप बीएसएनएलईयू पर आरोप लगाकर भुना रही है और सदस्यों में भय निर्मित कर रही है। इस संबंध में हम यहां स्पष्ट हमारे किसी भी साथी पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देगी। हमें आपके सहयोग और स्नेह और संघर्षशीलता पर पूर्ण विश्वास है। झूठ फैलाने वालों को, भय पैदा करने वालों को परास्त कीजिए।

बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन को मान्यता मिलने के बाद आपके सहयोग से लगातार संघर्षों के बाद प्राप्त उपलब्धियों पर एक नजर

★ बीएसएनएल की रक्षा की... सबसे अहम उपलब्धि

बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन और यूनाइटेड फोरम की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि, अभी तक बीएसएनएल की रक्षा की है तथा इसे सरकारी कम्पनी बनाकर रखा है। एनएफटीई ने कभी भी बीएसएनएल की पूरी बिरादरी को एक मंच पर लाने का न तो प्रयास किया था और न ही प्रयास कर सकती थी क्योंकि उसकी सोच ही इस प्रकार की नहीं है। यह बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन ही है, जिसने एकजीक्यूटिव और नान एकजीक्यूटिव कर्मचारियों को ज्वाइंट फोरम/ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाकर एक बैनर के नीचे संगठित किया। यह बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन ही है जिसने केजुवल और कान्ट्रेक्ट वर्कर्स का फेडरेशन बनवाया तथा उनके शोषण के विरुद्ध संघर्ष चलाने के साथ ही साथ बीएसएनएल की रक्षा करने के संघर्ष में शामिल करवाया। यह बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन ही है जिसने आल इंडिया बीएसएनएल डीओटी पेंशनर्स एसोसिएशन बनाकर पेंशन रिवीजन करवायी तथा पेंशनर्स साथियों को बी एस एन एल की रक्षा के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। यह बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन ही है जिसने बीएसएनएल को बेचने की सभी साजिशों को विफल किया है तथा बीएसएनएल का एक भी शेयर नहीं बिकने दिया है। इसके विपरीत, डी.ओ.टी के तीन टुकड़ों में से एक टुकड़ा व्हीएसएनएल (विदेश संचार निगम लिमिटेड) टाटा को बेच दिया गया है तथा दूसरा टुकड़ा एमटीएनएल बिकने की कगार में है।

किन्तु ज्वाइंट फोरम/ यूनाइटेड फोरम/ज्वाइंट एक्शन कमेटी एवं फोरम का गठन करने के लिए बीएसएनएलईयू द्वारा अपनाई गई सही कार्यशैली का ही परिणाम है कि बीएसएनएल आज भी सरकारी क्षेत्र की कम्पनी बनी हुई है तथा बीएसएनएल की 2 लाख 40 हजार (लगभग) की मानव शक्ति और उनके परिवार के हित सुरक्षित है। एनएफटीई द्वारा विगत 30–35 सालों से संचार के क्षेत्र की मानव शक्ति को देश की आम मजदूर – कर्मचारी बिरादरी से काटकर रखने के विपरीत, बीएसएनएलईयू ने संचार के कर्मचारियों को आम मजदूरों के संघर्ष में शामिल किया है तथा आम हड़तालों में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेकर

विशेष रूप से बीएसएनएल को बचाया है तथा आम रूप से आम जनता पर हो रहे हमलों का विरोध किया है। इसलिए यह सिद्ध हो गया है कि, यदि देश को बचाना है तो बीएसएनएल को बचाना चाहिए और यदि बीएसएनएल को बचाना है तो बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन को 10 मई 2016 के चुनाव में 50% से अधिक मतों से जिताना जरूरी है।

★ एमटीएनएल—बीएसएनएल का मर्जर रोका गया

सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया गया कि घाटे की कंपनी एमटीएनएल को बीएसएनएल में मर्ज कर दिया जाये लेकिन बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन एवं फोरम ने इसका कड़ा विरोध किया। यदि एमटीएनएल को बीएसएनएल में मर्ज किया जाता है तो बीएसएनएल और ज्यादा घाटे में चला जाता, जिससे वेतन रिवीजन की सम्भावनायें समाप्त हो जाती हैं लेकिन अभी वेतन रिवीजन की सम्भावनायें बरकरार हैं।

★ आईटीआई का बीएसएनएल में मर्जर रोका गया

जिस तरह एमटीएनएल घाटे की कम्पनी है उसी तरह आईटीआई भी घाटे की कम्पनी है सरकार आईटीआई को बीएसएनएल में मर्ज करना चाहती थी लेकिन बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन ने संयुक्त संघर्ष से आईटीआई का बीएसएनएल में मर्जर रुकवाया है।

★ टॉवर कम्पनी नहीं बनने वी गई है –

बीएसएनएल ने करोड़ों रूपये खर्च कर एवं बीएसएनएल के स्टाफ ने रात दिन मेहनत कर देश भर में 65000 टॉवर लगाये हैं लेकिन सरकार बीएसएनएल के टॉवर की अलग कम्पनी बनाकर बेच देना चाहती है अभी तक बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन ने संयुक्त संघर्षों के प्रयास से टॉवर कम्पनी नहीं बनने दी है।

★ 78.2 प्रतिशत आईडीए और एनएफटीई का दुष्क्रार एवं संघर्षों से पलायन

बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन ने यह सख्त रुख अपनाया था कि मूल वेतन में 78.2 प्रतिशत आई डी ए मर्ज करके ही नए वेतनमान बनाए जावें। इससे पहिले राव

कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुए मैनेजमेंट ने एकजीक्यूटिव के लिए 68.8 प्रतिशत आई डी ए मर्ज करके नए वेतनमानों की घोषणा कर दी थी। इसी बीच एनएफटीई ने देश भर में जोरदार प्रचार करना शुरू कर दिया कि बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन जान बूझकर वेतन समझौता करने में विलम्ब कर रही है। एनएफटीई ने ही मैनेजमेंट को लिखकर दे दिया कि जो एकजीक्यूटिव (अधिकारियों) को दिया है वही नान एकजीक्यूटिव को भी दिया जावे। (एकजीक्यूटिव को 68.8 प्रतिशत आईडीए मर्ज दिया गया था) एफएनटीई ने तो बाकायदा देश भर में अपनी मांग के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। इस परिस्थिति के कारण, वेतन समझौता में हो रहे विलम्ब से कर्मचारियों के काफी बड़े हिस्से में बेचैनी पैदा हो गई थी। इसलिए बीएसएनएलईयू ने बहुत ही सोच समझकर तुरन्त वेतन समझौता करने का निर्णय किया तथा यह भी निर्णय किया कि 78.2 प्रतिशत आई डी ए मर्जर की मांग के दरवाजे खुले रखे जावे। इसलिए वेतन समझौता में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया कि वेतन समझौता 68.8 प्रतिशत आईडीए मर्ज कर किया जावेगा किन्तु जब भी एकजीक्यूटिव को 78.2 प्रतिशत दिया जावेगा तो नान एकजीक्यूटिव को भी दिया जावेगा।

इस प्रकार, वास्तविक रूप से एनएफटीई द्वारा 68.8 प्रतिशत आईडीए मर्ज करके (एकजीक्यूटिव की तरह देने की मांग) एक तरफा नया वेतन घोषित करने की मांग के साथ ही 78.2 प्रतिशत आईडीए मर्ज करने को खत्म किया जा रहा था। बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन ने इसे एनएफटीई के मुँह से छीना है।

★ 01.01.2007 के पूर्व सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन रिवीजन:-

01.01.2000 को कम्पनी बनने की पूर्व संध्या पर सन 1972 के पेंशन नियम 37 में संशोधन करके नियम 37(ए) जोड़ा गया। यह संशोधन, एनएफटीई की सहमति से किया गया था। किन्तु संशोधन करते समय नियम 37 (8) में संशोधन नहीं किया गया।

यह नियम है कि, जब—जब केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन का पुनर्निधारण किया जावेगा तब तब पेंशन भोगियों की पेंशन भी रिवाइज्ड होगी। तदनुसार 01.01.06 से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा 01.01.07 से बीएसएनएल के कर्मचारियों

का वेतन पुनः निर्धारण हुआ। केन्द्र सरकार के पेंशन भोगियों की पेंशन भी रिवाइज्ड हुई। किन्तु डीओटी ने बीएसएनएल के 01.01.07 के पूर्व सेवा निवृत्त पेंशन भोगियों की पेंशन रिवाइज करने से, यह कहकर साफ इंकार कर दिया कि बीएसएनएल में आईडीए पर वेतन मिलता है तथा आईडीए के आधार पर पेंशन बनती है इसलिए आईडीए पर मिलने वाली पेंशन रिवाइज होने का कोई नियम नहीं है। किन्तु बी.एसएनएल ई.यू. और ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने संघर्ष किया तथा पेंशन रीविजन की मांग को प्रमुखता के साथ उठाकर अनेकों हड्डतालें की। इसलिए मजबूर होकर केन्द्र सरकार को पेंशन नियम 1972 37 (ए)(8) में संशोधन करना पड़ा। इस प्रकार दिनांक 01.01.2007 के पूर्व बीएसएनएल से सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन रिवाइज हुई तथा उन्हें डेढ़ लाख, 2 लाख तथा 3 लाख रूपये तक एरियर के रूप में प्राप्त हुए।

★ वेतन रिवीजन में सम्मान जनक वेतनमान मिला

यह पहिला अवसर है कि जब किसी कम्पनी ने नान एकजीक्यूटिव कर्मचारियों को एकजीक्यूटिव कर्मचारियों की तरह 30 प्रतिशत फिटमेंट फार्मूला का लाभ मिला है। यद्यपि सन 2009 से ही, बीएसएनएल घाटा दर्ज करने वाली कम्पनी हो गई थी, किन्तु बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन के नेतृत्व में यूनाइटेड फोरम द्वारा सही रास्ते पर चलकर लगातार संघर्ष चलाने का ही परिणाम था कि घाटे के बाद 15.01.2010 को वेतन समझौता पर हस्ताक्षर होने के बाद भी बीएसएनएल के कर्मचारियों को बेहतर और सम्मानजनक वेतनमान मिला। बीएसएनएल के 30 प्रतिशत फिटमेंट फायदे की तुलना में बैंक कर्मचारियों को सिर्फ 17.5 प्रतिशत का फिटमेंट लाभ ही मिल सका।

★ बीएसएनएलईयू ने शानदार प्रमोशन पालिसी (एन.ई.पी.पी.) हासिल की

एनएफटीई के दिल्ली का एक बड़े नेता एनईपीपी का पूरा नाम नान एकजीक्यूटिव पनिशमेंट पालिसी कह रहे थे। उनकी बात सुनकर हमें हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। किन्तु हमने यह सोचकर कुछ भी नहीं कहा कि छन्नी, ढोल—नगाड़ों के साथ पूरे नगर में घूम—घूम कर कहती फिरे कि, मुझमें एक भी छेद नहीं है, किन्तु पूरे नगर में उस पर विश्वास करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। बस छन्नी की ही तरह एनएफटीई के उस बड़े नेता का भी

हाल है।

क्या एनएफटीई के नेता इस बात से इंकार करेंगे कि, जब 2002–2004 के बीच में एनएफटीई को मान्यता थी तो उन्होंने मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया था कि 31.12.2006 तक कोई नई प्रमोशन पालिसी न बनाई जावे तथा ओटीबीपी और बीसीआर (दो प्रमोशन) की पालिसी ही प्रभावशील रहे।

यह, बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन तथा यूनाइटेड फोरम ही है जिसने 01.10.2000 (कम्पनी बनने की तारीख) से ही 5 प्रमोशन की शानदार प्रमोशन पालिसी हासिल की है। हां, यह बात सही है कि, दुनिया में कहीं भी जब भी कोई दूरगामी परिणाम देने वाली पालिसी बनेगी (चाहे वेतन आयोग हो) तो 100 प्रतिशत व्यक्तियों को तुरंत लाभ नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार एनईपीपी में भी पूरे देश में 97.36 प्रतिशत कर्मचारियों को फायदा हुआ है जबकि 2.64 प्रतिशत कर्मचारी इससे लाभान्वित नहीं हुए। किन्तु भविष्य में 100 प्रतिशत कर्मचारियों को 5 प्रमोशन की पालिसी का लाभ होगा।

प्रमोशन पालिसी के विषय में उल्टी-सीधी बात करने वाले एनएफटीई के नेताओं से हम कहना चाहते हैं कि वे डीजी पी एन्ड टी नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 43–19 / 84–पी–ई–1 दिनांक 09.04.1984 पढ़ें जिसमें उल्लेख है कि सन 1983 में एनएफटीई के साथ ओटीबीपी (एक प्रमोशन) का समझौता करके जो पद समाप्त किये गये हैं उससे सरकार को 12.3 करोड़ रुपये की बचत हुई है जबकि प्रमोशन पालिसी लागू करने से सरकार को सिर्फ 6.7 करोड़ रुपये ही खर्च करना पड़ेंगे।

बीएसएनएल ई यू एव यूनाइटेड फोरम द्वारा एक भी पोस्ट सरेंडर किये बिना एफ आर 22(1)(A)(1) के फायदे के साथ (ओटीबीपी–बी सी आर में एफ आर 22 (1)(A)(1) नहीं था) पांच प्रमोशन हासिल करना कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

★ सम्मान जनक पदनाम परिवर्तन

अंग्रेज शासक, भारतीयों को “मेन” कहा करते थे। इसलिए ज्योंही देश में उद्योग–धंधे, जैसे रेल टेलीग्राफ आदि पैदा हुए त्योंही भारतीयों की नौकरियाँ प्राप्त हुई एवं अंग्रेजों ने उन्हें पदनाम दिए। चूंकि अंग्रेज शासक भारतीयों

को सिर्फ मेन से आगे कुछ नहीं कहना चाहते थे इसलिए उन्होंने उन्हें रेलवे मेन, गेट मेन, लाइन मेन, वायर मेन, केबिन मेन, लिफ्टमेन वाटरमेन, टेलीग्राफ मेन आदि–आदि पदनाम दिए। एनएफटीई ने अनेकों साल तक मान्यता में रहने के बाद भी कभी भी पदनामों में बदलाव करने की मांग नहीं उठाई। किन्तु मान्यता मिलने के बाद, बीएसएनएलईयू ने सम्मानजनक पदनाम देने की मांग की तथा अंग्रेजों की परम्परा को समाप्त करने के लिए आवाज उठाई। अनेकों दौर की चर्चाओं के बाद रेगुलर मजदूर का पदनाम असिस्टेंट “टेलीकाम टेक्नीशियन”, टेलीकाम मैकेनिक का पदनाम “टेलीकाम टेक्नीशियन”, टीटीए का पदनाम “जूनियर इंजीनियर” एवं वरिष्ठ कार्यालय सहायक के लिए एनई–7 और एनई–8 वेतनमान में सीनियर टीओएज को “सीनियर ऑफिस एसोसिएट्स” का नया पदनाम और जो एनई–9 एनई–10 वेतनमानों में हैं उन्हें ‘एसिस्टेंट आफिस सुपरिटेंडेंट’ का पदनाम दिया जायेगा। एनई–11 और एनई–12 के वेतनमानों वाले सीनियर टीएओज को ‘ऑफिस सुपरिटेंडेंट’ का नाम दिया गया है।

★ ऑफीशिएटिंग जेटीओज के लिए नियमित प्रमोशन

ऑफीशिएटिंग जेटीओज के लिए नियमित प्रमोशन काफी समय से लंबित समस्या थी। लगभग 1800 उम्मीदवारों जिन्होंने 2000 में जेटीओ स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया था वे प्रमोशन न मिलने की समस्या से पीड़ित रह रहे हैं। यह बीएसएनएलईयू थी जिसने इस मांग को लगातार उठाया कि सभी ऑफीशिएटिंग जेटीओज को नियमित प्रमोशन दिया जाये। बीएसएनएलईयू ने इस मुद्दे को नेशनल काउंसिल मीटिंग में उठाया। बीएसएनएलईयू ने आरंभ में मांग की कि आफीशिएटिंग जेटीओज को व्यक्तिगत अपग्रेडेशन के माध्यम से नियमित जेटीओ प्रमोशन दिया जाये। प्रबंधन इस मुद्दे को हल नहीं कर सका चूंकि माननीय चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में एक केस काफी समय से लंबित था। उस केस के खत्म होने के बाद बीएसएनएलईयू ने पुनः इस मुद्दे को प्रबंधन के साथ उठाया और सभी ऑफीशिएटिंग जेटीओज को फौरन नियमित प्रमोशन देने की मांग की। इस मांग को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने संशोधित जेटीओ आर आर फाइनल किये। इस आरआर के अनुसार आफीशिएटिंग जेटीओज

को नियमित प्रमोशन देने के लिए जेटीओ पदों की आवश्यक संख्या उपलब्ध कराई गई। इस समझौते के जरिए लगभग 1500 आफीसिएटिंग जेटीओज को लाभ हुआ है। वे सभी इस समय ट्रेनिंग कर रहे हैं या ट्रेनिंग अपने अंतिम चरण में हैं। यह बीएसएनएलईयू की एक और उपलब्धि है।

★ संशोधित जेटीओ भर्ती नियम

जेटीओ परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक क्वालीफाइंग सेवा पहले 10 वर्ष थी। यह बीएसएनएलईयू थी जिसने इस मुद्दे को उठाया और उसे 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष कराया। फिर भी 7 साल बहुत लंबी अवधि थी। इसलिए बीएसएनएलईयू ने मांग की कि कर्मचारियों को 4 साल की सेवा पूरी होने पर जेटीओ एलआईसीई में बैठने की इजाजत दी जाये। इस मुद्दे पर नेशनल काउंसिल में चर्चा की गई और यह अनेक संघर्षों में एक महत्वपूर्ण मांग भी रही। अंत में प्रबंधन क्वालीफाइंग सेवा को कम करके 5 साल करने के लिए सामने आया। उसके अनुरूप जेटीओ भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है। अब सभी टीटीएज और अन्य श्रेणी के कर्मचारी 5 साल की क्वालीफाइंग सेवा पूरी करने पर जेटीओ एलआईसीई में बैठ सकते हैं। इससे आगामी जेटीओ एलआईसीई में बैठने हेतु पात्र हजारों सीधी भर्ती टीटीएज को लाभ हुआ है। इस प्रकार जेटीओ एलआईसीई में बैठने के लिए क्वालीफाइंग सेवा में 7 वर्ष से कम करके 5 वर्ष कराना बीएसएनएलईयू की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

★ बीएसएनएल में सीधे भर्ती कर्मचारियों के लिए पेंशन

डीपीई के निर्देशों अनुरूप बीएसएनएल को सीधे भर्ती कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों और कर्मचारी के वेतन का 30 प्रतिशत अंशदान देना चाहिए। प्रबंधन पहले ईपीएफ, ग्रेचुटी और पोस्ट रिटायरमेंट मेडीकल बेनीफिट्स (पीआरएसबी) की ओर वेतन का 18 प्रतिशत अंशदान दे रही है। इसलिए वेतन का बकाया 12 प्रतिशत पेंशन फंड में अंशदान देना चाहिए। बीएसएनएलईयू फोरम के साथ मिलकर इस मुद्दे को लगातार प्रबंधन के साथ उठा रही है। शुरू में, कंपनी के वित्तीय संकट की बात कहकर प्रबंधन ने पेंशन फंड में वेतन के 2 प्रतिशत का अंशदान का प्रस्ताव रखा था। किन्तु बीएसएनएलईयू और फोरम ने इस

प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह मुद्दा 21 और 22 अप्रैल 2015 को हुई 2 दिन की हड़ताल में एक प्रमुख मांग के रूप में भी सामने आया। बाद में प्रबंधन वेतन के 3 प्रतिशत का अंशदान करने के लिए सामने आया। बाद में प्रबंधन वेतन में 3 प्रतिशत का अंशदान करने के लिए सहमत हुआ। इसे भी बीएसएनएलईयू और फोरम ने अस्वीकार कर दिया। बीएसएनएलईयू और फोरम द्वारा अपनाए गए सख्त रुख के कारण प्रबंधन पेंशन फंड का और वेतन के 6 प्रतिशत का अंशदान देने के लिए राजी हुआ है। अब इसे कार्पोरेट ऑफिस में प्रोसेस किया जा रहा है और शीघ्र ही इसे बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की स्वीकृती के लिए भेजा जाएगा। बीएसएनएलईयू इस बात पर गर्व कर सकती है कि उसने सीधे भर्ती कर्मचारियों के पेंशन के मुद्दे के हल में महत्वपूर्ण योगदान किया है। शेष 6% की लड़ाई भी जारी रहेगी।

★ अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ –

उन कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ हासिल करने में भारी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ रहा है जिनका सेवारत रहते हुए निधन हो गया। मुख्य रुकावट पदों की उपलब्धता है। यह समस्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पैदा हुई है। उसके फैसले के अनुसार एक वर्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे गये पदों के सिर्फ 5 प्रतिशत को अनुकंपा आधारित नियुक्तियों के लिए रखा जा सकता है।

★ सीजीएम को पुनः अधिकार दिए गए :-

बीएसएनएलईयू अनुकंपा आधारित नियुक्तियों के केस में परेशानियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है। यूनियन नेशनल काउंसिल के अंदर और बाहर दोनों जगह मुद्दें को लगातार उठा रही है। इसके फलस्वरूप अनुकंपा आधार पर नियुक्तियाँ करने के अधिकार पुनः चीफ जनरल मैनेजर्स को दे दिये गये हैं। इस प्रकार कार्पोरेट ऑफिस की उच्चाधिकार कमेटी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जो भारी देरी अनुभव की गई है उसे दूर कर दिया गया है। उम्मीदवारों के लिए यह एक बड़ी राहत है।

★ दुर्घटना केस में त्वरित अनुकम्पा नियुक्ति

अनुकंपा आधारित नियुक्तियों से जुड़ी एक बहुत ही गंभीर समस्या दुर्घटनाओं में दिवंगत हुए कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार न मिलना है। बड़ी संख्या में लाइन

स्टाफ ड्यूटी पर दुर्घटनाओं में दिवंगत है जैसे टेलीफोन पोस्टो से गिरना, बिजली का करंट लगाना, सड़क दुर्घटना आदि। किन्तु जब इन कर्मचारियों के आश्रित अनुकंपा आधारित रोजगारों के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इसकी बजाय उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है। बीएसएनएलईयू ने 16.10.2015 को हुई नेशनल काउंसिल की 33वीं मीटिंग में केस को कडाई के साथ उठाया। बीएसएनएलईयू ने मजबूत तर्क दिए कि ड्यूटी पर दुर्घटना में मारे गये कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा आधारित नियुक्तियां देने में प्राथमिकता दी जाये। प्रबंधन पक्ष ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। कार्पोरेट ऑफिस इस पर काम कर रही है और शीघ्र ही अनुकंपा आधारित नियुक्तियों के लिए गाइडलाइनों में ड्यूटी पर दुर्घटना में दिवंगत हुये कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने के लिए परिवर्तन किया जायेगा।

★ एससी/एसटी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा बीएसएनएलईयू के सतत प्रयास

बीएसएनएलईयू लगातार कोशिश रही है कि बीएसएनएल में विभागीय परीक्षाओं में एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए आरक्षण पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेशों को लागू किया जाये। इस मुद्दे पर नेशनल काउंसिल मीटिंग में एक से अधिक बार चर्चा हुई है जिसके फलस्वरूप एक कमेटी गठित की गई है। इसके अनुरूप टेलीकाम मैकेनिक और टीटीए कैडर के लिए एलडीसीईज के औसत मार्कर्स को 25 प्रतिशत से घटाकर 23 प्रतिशत किया गया। यहां इस बात का उल्लेख करना अत्याधिक प्रासंगिक है कि यह केवल बीएसएनएलईयू ही है जो लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रही है कि बीएसएनएल में एससी/एसटी कर्मचारियों के जायज और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाये।

★ बीएसएनएल एमआरएस में सुधार हेतु सुझाव

बीएसएनएलईयू की यह मांग है कि बीएसएनएल एमआरएस के कर्मचारियों की परेशानियों को दूर करने के लिए एक कमेटी गठित की जाये। 32वीं नेशनल काउंसिल मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और एक समीक्षा कमेटी गठित करने की सहमति हुई। इसी के अनुरूप एक कमेटी गठित की गई। जनरल सेक्रेटी बीएसएनएलईयू और जनरल सेक्रेट्री एनएफटीई इस कमेटी में स्टाफ पक्ष के

सदस्य हैं। कमेटी की पहली मीटिंग 08.01.2016 को हुई। इस मीटिंग में का. पी. अभिमन्यु जनरल सेक्रेट्री ने इंगित किया कि बीएसएनएल के साथ समझौता करने के लिए सीजीएचएस दरें बहुत कम हैं। बीएसएनएल के साथ समझौता करने के लिए प्रतिष्ठित अस्पताल तैयार नहीं थे। इसके अलावा, कई अच्छे अस्पताल, बीएसएनएल कर्मचारियों को चिकित्सा प्रदान नहीं करना चाहते क्योंकि बीएसएनएल द्वारा बिलों के भुगतान में असामान्य देरी की जाती है। हमें उम्मीद है कि बीएसएनएल एमआरएस के तहत इलाज कराने के संबंध में कर्मचारियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें हल करने के लिए तरीके और साधन निकाल लिए जायेंगे।

★ बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए नयी सामूहिक बीमा योजना

बीएसएनएलईयू की पहल पर 1.8.2005 में नान-एकजीक्यूटिव के लिए एक लाख (दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में 2 लाख) के बीमे के साथ बीएसएनएल-जीएसएलआईएस की शुरूआत हुई। पूर्व में ग्रुप डी के लिए 15000 रुपये का बीमा तथा ग्रुप सी के लिए 30000 रुपये का बीमा था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सामूहिक बीमा योजना है।

★ सीजीईजीआईएस बचत फण्ड का भुगतान

सीजीईजीआईएस बचत फण्ड के भुगतान की मांग को एनएफटीई ने यह कहकर जटिल बना दिया कि मृत्यु या सेवानिवृत्ति से पूर्व इस फण्ड का भुगतान नहीं किया जा सकता। परन्तु लगातार संघर्ष और प्रयास के चलते डीओटी ने दिनांक 25.10.2006 को सी जी ई जी आई एस बचत फण्ड भुगतान के लिए आदेश जारी किया। सीजीईआईएस 1977 के भुगतान का आदेश भी 23.7.2008 को जारी किया गया।

★ (1.10.2000) के बाद बीएसएनएल में अब्जार्ब टीएसएम को प्रेसीडेंशियल आर्डर तथा सरकारी पेंशन पात्रता

ऐसे आकस्मिक मजदूर जो 1.10.2000 को या उसके बाद भर्ती हुए, को प्रेसीडेंशियल आर्डर तथा उससे संबंधित लाभ दिलाने के लिए बीएसएनएलईयू ने मुददा लिया। अन्त में बीएसएनएल तथा डीओटी स्तर पर लगातार प्रयास के बाद दिनांक 20.10.2006 को 1.10.2000 के बाद भी बीएसएनएल में अब्जार्ब टीएसएम को पीओ जारी करने

तथा सरकारी पेंशन पात्रता का आदेश जारी किया गया । बीएसएनएलईयू द्वारा मामला डीओटी स्टेंडिंग कमेटी में उठाने के बाद अब प्रेसीडेंशियल आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

★ पीएसयू बैंकों से सुलभता से लोन की सुविधा

यह महसूस करते हुए कि बीएसएनएल से मिलने वाला लोन पर्याप्त नहीं है बीएसएनएलईयू ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से कम ब्याज दर पर लोन दिलाने के लिए पहल की । प्रबन्धन तथा बीएसएनएलईयू की संयुक्त समिति गठित की गई तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से समझौता करके कर्मचारियों के लिए लाभप्रद बैंक लोन स्कीम लागू की गयी । सिर्फ पहले 6 महीने में कर्मचारियों द्वारा 3 करोड़ से भी अधिक लोन लिया गया । शुरुआती समझौता अगले एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया ।

★ फूड भत्ता

1.1.2005 से फूड भत्ता(खुराक भत्ता) के नाम से एक नया भत्ता लागू किया गया ।

★ ग्रामीण प्रति पूरक भत्ता

1.1.2015 से वे कर्मचारी, जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं जो कि अनकलासीफाईड है, 100 रुपये की दर से एक नया ग्रामीण प्रतिपूरक भत्ता पाने के हकदार हैं ।

★ त्यौहार अग्रिम में बढ़ोत्तरी

त्यौहार अग्रिम 1500 रुपये से बढ़कर 5000 रुपये हुआ ।

★ सेवानिवृत्ति बिदाई उपहार

बीएसएनएलईयू की मांग पर वेलफेयर कमेटी ने 1001 रुपये की दर से लागू किया, पुनः बीएसएनएलईयू की मांग पर बढ़ाकर 2001 रुपये की दर से कर दिया । बाद में उसे पुनः बढ़ाकर 3001 कराया गया । इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के दिन उपहार तथा स्वागत के साथ छुट्टी नकदी, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान किया जा रहा है । ये सभी आदेश बीएसएनएलईयू की मांग पर किये गये हैं ।

★ ट्रांसपोर्ट भत्ते में वृद्धि

बीएसएनएलईयू की मांग पर ए-1 तथा ए क्लास शहरों में 100 रुपये से 300 रुपये तथा अन्य सभी शहरों में 75 रुपये से 225 ट्रांसपोर्ट भत्ता दिनांक 1.1.2005 से बढ़ाया गया ।

★ ग्रेड-4 के ट्रांसपोर्ट भत्ते में बढ़ोत्तरी

दिनांक 1.1.2005 से ए-1 तथा ए क्लास शहरों में 400 रुपये से 750 रुपये तथा अन्य सभी शहरों में 200 रुपये से

475 रुपये ग्रेड-4 के लिए ट्रांसपोर्ट भत्ता बढ़ाया गया । आदेश 8.3.2007 को जारी हुआ ।

★ विकलांग कर्मचारियों का ट्रांसपोर्ट भत्ता बढ़ावाकर 1000 रुपये करवाया गया

★ बीएसएनएल में भर्ती कर्मचारियों के लिए रेन्ट फी आवासीय टेलीफोन सुविधा

बीएसएनएल द्वारा भर्ती किये गये नये कर्मचारी इस सुविधा से वंचित थे । बीएसएनएलईयू ने प्रबन्धन के साथ मामला उठाया । नये भर्ती कर्मचारियों को इस सुविधा की स्वीकृति का आदेश 15.4.2005 का जारी किया गया ।

★ फी कालों में बढ़ोत्तरी

ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए बढ़ी हुई फी काल 150 तथा ग्रुप सी के लिए 200 फी काल का आदेश जारी किया गया ।

★ बकाया टेलीफोन बिल राशि वसूल करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति

बीएसएनएलईयू की मांग पर स्थायी रूप से बन्द बेसिक टेलीफोन डब्ल्यू एल एल , सीएमटीएस के सम्बन्ध में बकाया टेलीफोन बिल राशि की उगाही के लिए कर्मचारियों को प्रतिभूति की स्वीकृति का आदेश 30.1.2008 को जारी ।

★ टीटीए संवर्ग के वेतनमान का पुनर्निर्धारण

1.10.2000 से टीटीए संवर्ग के सी डी ए 4500–7000 से सी डी ए 5000–8000 में वेतन निर्धारण तथा सीडीए से आई डी ए में वेतन निर्धारण में विसंगति । संयुक्त समिति के प्रयास के बाद 24.9.2008 को आदेश जारी ।

★ स्कालरशिप में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी

वेलफेयर कमेटी में चर्चा के उपरान्त स्कालरशिप की राशि में बढ़ोत्तरी । आदेश जारी ।

★ वेलफेयर फण्ड की स्वीकृति

बीएसएनएल ई यू की मांग पर सेवा में रहते हुए मृत्यु के मामले में वेलफेयर फण्ड 10000 से बढ़ाकर 15000 हुआ ।

★ उच्च श्रेणी में इलाज के लिए अनुमति

यदि कर्मचारी की पात्रता के अनुसार कक्ष उपलब्ध नहीं है तो उच्च श्रेणी के कक्ष में इलाज कराने सम्बन्धी आदेश 17.10.2007 को जारी ।

★ स्थानांतरण पर स्टाफ क्वार्टर रिटेन्शन

बीएसएनएलईयू द्वारा मामला उठाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित कर्मचारियों के लिए मौजूदा स्टेशन पर स्टाफ क्वार्टर रिटेन्शन के लिए प्रबन्धन सहमत और आदेश जारी ।

★ खिलाड़ियों की नियुक्ति

खिलाड़ी कोटे की रिक्तियों पर 400 से अधिक खिलाड़ियों की नियुक्ति बैकलाग रिक्तियों भरने के लिए भी दिनांक 30.3.2007 आदेश जारी।

★ खिलाड़ियों की प्रोन्नति

यूनियन के लगातार प्रयास के बाद स्पोर्ट कोटे में भर्ती कर्मचारियों के प्रमोशन सम्बन्धी आदेश जारी।

★ खिलाड़ियों के लिए किट मनी, रिफ्रेशमेंट चार्ज, दैनिक भत्ता बढ़वाये गये

★ प्रमोशन के अवसर... विभागीय परीक्षायें

बीएसएनएलईयू ने जहां पांच प्रमोशन पॉलिसी लागू करवाईं वहाँ लगातार विभागीय परीक्षायें जेटीओ, जेएओ फोन मैकेनिक, टीटीए हिन्दी ट्रांसलेटर आदि लगातार आयोजित करवायी गई जिससे हजारों कर्मचारियों को फायदा हुआ।

★ डी.सी.आर.जी. (रिटायरमेंट में ग्रेच्युईटी का भुगतान)

रिटायरमेंट में मिलने वाली ग्रेच्युईटी 3.5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करवाया गया।

अन्य सुविधाएँ

★ परिवार के सदस्य यदि दूसरे शहर में रहते हैं तो उनके लिए अलग से मेडीकल कार्ड बनाने का आदेश जारी करवाया गया।

★ रिटायरमेंट में 33 साल की जगह 20 साल की सर्विस में पूर्ण पेंशन देने का आदेश जारी करवाया गया।

★ बीएसएनएल में सीधे भर्ती कर्मचारियों के लिए रेन्ट फ़ी टेलीफोन की सुविधा। फ़ीकॉल में बढ़ोत्तरी करवायी गई।

★ ब्राउडबैंड कनेक्शन में चार्ज में रियायत (छूट) दिलवायी गई।

★ चाइल्ड केयर लीव (महिलाओं के लिए) का प्रावधान कराया गया।

बी.एस.एन.एल.ई.यू. का एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन बनाना वर्तमान समय की जरूरत

आने वाले दिन बहुत ही निर्णायक हैं। कर्मचारियों द्वारा अपने संयुक्त संघर्षों के जरिए बीएसएनएल ने पुनरुद्धार के लिए किये गये प्रयत्नों का अच्छा नतीजा आना शुरू हो गया है। बीएसएनएल ने परिचालन लाभ कमाना आरंभ कर दिया है और मोबाइल क्षेत्र में उसकी परफार्मेंस बहुत ही उत्साहवर्धक है। इन धनात्मक कार्यक्रमों को मजबूत करना होगा। एनडीए सरकार भारतीय और बहुराष्ट्रीय निगमों के लाभ के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसी के अनुरूप एनडीए सरकार ने एक सहायक टॉवर कंपनी बनाने का निर्णय लिया है जो बीएसएनएल को कमज़ोर करने के अलावा और कुछ नहीं है। कर्मचारी 1.1.2017 से लागू होने वाले अगले वेतन संशोधन का उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं। बीएसएनएल कर्मचारी अगले वेतन संशोधन के पूरी तरह अधिकारी हैं। इससे वंचित करने के किसी भी प्रयत्न को इस तर्क के आधार पर कि कंपनी को घाटा हो रहा है, पूरी तरह शिकस्त देनी होगी। यह सच है कि हम केवल संयुक्त संघर्षों के जरिए ही कंपनी और कर्मचारियों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। किन्तु साथ ही संयुक्त संघर्ष चलाने के लिए एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन (सिर्फ एक मान्यता प्राप्त यूनियन) की जरूरत है। इस कर्तव्य का बीएसएनएलईयू ने पिछले 11 साल से अधिक समय की अवधि में जोरदार तरीके से पालन किया है। बीएसएनएलईयू आने वाले दिनों में भी इस नेतृत्वकारी और एकजुट करने वाली भूमिका को अदा करने का आश्वासन देती है। अतः हम कर्मचारियों से बीएसएनएलईयू को 51 प्रतिशत से अधिक वोट देकर एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन बनाने की अपील करते हैं।

78.2% IDA मर्जर के आधार पर विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षण एवं LTC के पुनर्बहाली की मांग

दिनांक 4.3.2016 को सम्पन्न फोरम की मीटिंग में लिए गए निर्णय अनुसार फोरम के संयोजक कॉ.पी अभिमन्यु द्वारा सीएमडी श्री अनुपम श्रीवास्तव को पत्र लिखकर निम्न मांग की गई। ज्ञातव्य है कि 10.6.2013 से 78.2% IDA मर्जर के आधार पर हमारा पुनः वेतन पुनरीक्षण हुआ था। फोरम के साथ हुए एग्रीमेंट में प्रबंधन द्वारा कुछ समय पश्चात विभिन्न भत्तों को 78.2% IDA मर्जर के आधार पर पुनरीक्षित करने का आश्वासन भी दिया गया था किन्तु 2.5 वर्ष के अंतराल के बाद भी मांग लंबित है। हाल ही में सभी कर्मचारियों के योगदान से बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति में प्रशंसनीय सुधार हुआ है। अतः फोरम की ओर से 78.2% IDA मर्जर के आधार पर भत्तों के शीघ्र पुनरीक्षण की मांग की गई है।

इसी प्रकार LTC सुविधा पर रोक लगे हुए 5 वर्ष बीत चुके हैं। बीएसएनएल में डेप्यूटेशन पर पदस्थ ITS अधिकारी तो LTC सुविधा का लाभ ले रहे हैं किन्तु बीएसएनएल के अपने कर्मचारी अधिकारी इस सुविधा से वंचित हैं। प्रबंधन का यह रवैया पूरी तरह अनुचित है। अतः LTC सुविधा बीएसएनएल कर्मियों के लिए भी शीघ्र बहाल की जाए।

समस्याएं : निदान हेतु परिमंडल द्वारा किए गए प्रयास एवं परिणाम

मध्यप्रदेश परिमंडल के नव – नेतृत्व ने सचिव मंडल के सहयोग से प्राप्त समस्याओं के निदान हेतु त्वरित संज्ञान लेते हुए अधिकांश के संतोषजनक निदान हेतु सक्रियता का परिचय देते हुए अपनी भूमिका का सफलतम निर्वहन करने की कार्यकारिणी की है। 9.8.2015 को नव निर्वाचित कार्यकारिणी के सहयोग से “सामूहिक नेतृत्व” की नव अवधारणा को केवल शब्दों में ही नहीं बरन मूर्त रूप में भी साकार रूप प्रदान करते हुए निम्न समस्याओं का निदान किया है।

टीटीए रिजल्ट रिव्यू

आदेश जारी – 7.6.2013 को संपन्न टी टी ए LICE में 7 आऊट ऑफ सिलेबस प्रश्नों के एवज में 7 अतिरिक्त अंक देकर रिजल्ट रिव्यू करने हेतु आदेश जारी हुए। निःसंदेह इसमें सीएचक्यू की अहम भूमिका है किन्तु परिमंडल ने अपने स्तर पर प्रबंधन एवं सीएचक्यू से संपर्करत रहते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन किया है।

दमोह में मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल की सुविधा

दमोह में अब तक एक भी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जिला सचिव दमोह को भगवानदास से प्राप्त जानकारी के आधार पर परिमंडल द्वारा मुख्य महाप्रबंधक महोदय को पत्र लिखकर एवं विभिन्न बैठकों में चर्चा कर दमोह प्रबंधन द्वारा अनुशंसा कर प्रेषित हॉस्पिटल को मान्यता हेतु पत्र जारी किया गया।

पन्ना एस एस ए की समस्याओं का निदान

विगत दो वर्षों से लेखा अधिकारी पन्ना में उपलब्ध न होने से वहां के साथियों को अपने भुगतान व अन्य एच आर इश्यूज को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहां लेखा अधिकारी भी पदस्थ किए गए और तत्पश्चात् सतना टीडीएम पर पन्ना की निर्भरता को खत्म करवाने में परिमंडल यूनियन को सफलता मिली।

मुरैना की समस्याओं के निदान में सहयोग

मुरैना की दो घटनाओं में परिमंडल तत्काल संज्ञान लेकर न्यायप्रद निर्णय करवाने में कामयाब रहा है। श्योपुर में गेम्बलिंग की घटना में कुछ अधिकारियों के अनुचित दबाव को प्रभावहीन किया गया। और हमारे जिला सचिव के सुझाव अनुसार अपेक्षानुरूप कार्यवाही हुई। इसके अलावा हाल ही में एक DSA द्वारा हमारे TTA साथी के साथ किए गए दुर्व्यवहार एवं अधिकारियों द्वारा हमारे पदाधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के प्रयास को विफल किया गया। इन दोनों

ही प्रकरणों में तत्काल हस्तक्षेप से जहां हमारे नेतृत्व का मनोबल बढ़ा वहीं आम सदस्यों में भी हमारी सकारात्मक छवि बनी है। जिला सचिव कॉडी एस भदोरिया एवं जिला अध्यक्ष कॉ आर.एस. शर्मा निरंतर परिमंडल सचिव से संपर्करत रहे जिससे समस्या का निदान करना सहज हो सका। उन्हें धन्यवाद।

राजगढ़ व्यावरा अब भोपाल झोन में

राजगढ़ जिला सचिव कॉ अरविंद व्यास एवं जिला अध्यक्ष कॉ बी एम यादव ने परिमंडल सचिव को राजगढ़ व्यावरा ग्वालियर झोन में होने से भौगोलिक दूरी के मद्देनजर होने वाली परेशानियों से अवगत करवाया। ज्ञातव्य है कि राजगढ़ की भोपाल से दूरी महज 116 किमी है वहीं ग्वालियर की 350 किमी। परिमंडल सचिव द्वारा इस इश्यू को तत्परता से मुख्य महाप्रबंधक के ध्यान में लाया गया, कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत करवाया गया, पत्र भी लिखे गए। माननीय मुख्य महाप्रबंधक ने हमारे अनुरोध को स्वीकारते हुए राजगढ़ ग्वालियर झोन से पृथक कर भोपाल झोन में समाहित किए जाने के आदेश जारी किए।

रीवा प्रकरण का निदान

रीवा में हुए अपने आप में अनोखे प्रकरण में परिमंडल सचिव ने बेहद सूझबूझ का परिचय देते हुए इसके निदान हेतु प्रयास किए। इस प्रकरण में म.प्र. फोरम भी पूर्ण रूप से सहयोगी रहा।

हमारी परिपक्वता, संघर्षशीलता, एकता को भांपते हुए म.प्र. परिमंडल प्रबंधन ने टीडीएम रीवा का स्थानांतरण कर मामले को शांत करने में सहयोग दिया। यूनियन के प्रयासों की वजह से हमारे सहयोगी टीटीए का रीवा के बाहर हो चुका स्थानांतरण भी रद्द हुआ। यह एक पेचीदगी भरा प्रकरण था। हमारे जिला सचिव के लिए भी यह संकटपूर्ण एवं दुविधाजनक स्थिति थी। किन्तु इस प्रकरण के संतोषजनक पटाक्षेप में रीवा के जिला सचिव कॉ पुष्पेन्द्र सिंह ने बेहद सूझबूझ का परिचय दिया। उनका आभार।

खंडवा : स्थानांतरण पर रोक

खंडवा के हमारे कुछ साथियों के स्थानांतरण आदेश म.प्र. परिमंडल की नई कार्यकारिणी के गठन के पूर्व किए गए थे। इन स्थानांतरण प्रकरणों में खंडवा जिला सचिव कॉ पी एल सामरे के अनुसार पक्षपात पूर्व कार्यवाही प्रबंधन द्वारा की गई थी। स्थानांतरण आदेश में अनियमितताएं होने से प्रबंधन स्वयं कन्फ्यूज था। इसलिए आदेश कभी हेल्ड इन अबेयंस रखे गए, कभी रिलीव आदेश जारी किए गए, फिर पुनः स्थगित किए

गए। इस अराजक स्थिति से परिमंडल प्रबंधन को परिमंडल सचिव द्वारा अवगत करवाया गया। विभिन्न मुलाकातों के दौरान चर्चा भी की गई। अंतगोत्वा इन आदेशों पर रोक लगाने में हम सफल हुए। जिला सचिव कॉ. पी एल सामरे एवं कॉ. संतोष चौरसिया की इस प्रकरण के निदान हेतु सक्रियता प्रशंसनीय रही।

जबलपुर : स्थानांतरण प्रकरणों में अर्ध – सफलता

जबलपुर जिला सचिव कॉ. अरजसिया द्वारा हमारे दो साथियों कॉ. मोतीलाल रैदास एवं कॉ. अनिल कश्यप के स्थानांतरण प्रकरण परिमंडल को प्रेषित किए गए थे। कॉ. मोतीलाल रैदास एक लंबे समय से (लगभग 4 माह से अधिक) अवकाश पर थे। उनके स्थानांतरण आदेश परिमंडल के हस्तक्षेप से निरस्त हुए। इस बाबद परिमंडल प्रबंधन को कड़ा पत्र भी लिखा गया था। किन्तु कॉ. अनिल कश्यप का स्थानांतरण आदेश अभी तक निरस्त नहीं हो सका है। इस लिहाज से जबलपुर स्थानांतरण प्रकरण को हम अर्ध सफलता मान सकते हैं।

सतना रीवा, एवं सागर के आंदोलन में सहयोग

स्थानीय मुद्दे, प्रबंधन की कुछ मुद्दों को लेकर हठधर्मिता, पक्षपातपूर्ण रवैय्या, यूनियन द्वारा प्रस्तुत समस्याओं की अनदेखी आदि विभिन्न कारणों की वजह से हमारी सतना, रीवा सवं सागर की जिला इकाईयों को आंदोलनात्मक स्थिति के लिए मजबूर होना पड़ा। संबंधित जिला सचिवों द्वारा अपने अपने जिला प्रमुखों की आंदोलन नोटिस को लेकर उदासीनता के चलते परिमंडल से हस्तक्षेप का आग्रह किया गया। परिमंडल सचिव द्वारा स्थिति का त्वरित संज्ञान लिया गया और जिला सचिवों की अपेक्षानुरूप कार्यवाही की गई। इसी प्रकार ग्वालियर में भी एसएसए प्रमुख के व्यवहार को लेकर जिला इकाई में रोष व्याप्त था। यहां भी हमारी सकारात्मक दखल अंदाजी से मामले का संतोषजनक निपटान हुआ। सभी प्रकरणों में मुख्य महाप्रबंधक महोदय का बेहद सहयोगात्मक रुख रहा।

खजुराहो नेटवर्क सुविधा एवं हॉलीडे होम/हट

छतरपुर से कॉ. सत्येन्द्र जैन द्वारा खजुराहो में नेटवर्क की बदहाली का मुद्दा प्रेषित किया गया था। इस संबंध में 14/8/2015 के सेमीनार में मुख्य महाप्रबंधक महोदय को समस्या से अवगत करवाया एवं निदान की मांग की गई।

खजुराहो में हट/हॉलीडे होम सुसज्जित कराने हेतु भी विभिन्न बैठकों में प्रयास किए गए।

मेडिकल अदालत

मुख्य महाप्रबंधक द्वारा मेडिकल अदालत का अनूठा प्रयोग

मध्यप्रदेश में पहली बार किया गया। अदालत में बकाया मेडिकल बिलों का भुगतान शतप्रतिशत रूप से हो गया ऐसा तो नहीं कहा जा सकता किन्तु जिस तरह से विगत वर्षों में मेडिकल बिलों की अनदेखी की गई थी, उस व्यवस्था में सुधार आया है। कुछ बहुत पुराने बिल्स का निपटान भी हुआ है किन्तु अभी भी स्थिति में और सुधार अपेक्षित है। कुछ बिल भी या तो सर्कल ऑफिस या संबंधित एसएसए से गुम होने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं।

इसका संज्ञान परिमंडल यूनियन द्वारा लिया गया है। और सुधार – प्रक्रिया हेतु प्रबंधन के ध्यान में भी लाया गया है। बिल भुगतान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कुछ सुझाव भी परिमंडल प्रबंधन को दिए गए हैं – किन्तु इसे गंभीरता से नहीं लिया गया प्रतीत होता है। इस हेतु परिमंडल यूनियन ठोस कार्यवाही करेगी।

जीपीएफ भुगतान विशेष प्रयास

ज्ञातत्व है कि विगत समय में कुछ महीनों में जीपीएफ भुगतान में फंड के अभाव में कुछ विलम्ब हुआ था। फंड हेतु प्रत्येक माह हमारे महासचिव द्वारा कार्पोरेट ऑफिस में विशेष प्रयास किए जाते हैं। उसके बाद ही फंड रिलीज होता है।

मध्यप्रदेश परिमंडल में कई एसएसए में आउट ऑफ टर्न “जीपीएफ भुगतान हेतु परिमंडल यूनियन द्वारा अतिरिक्त प्रयास कर भुगतान करवाया गया है। हमारे जिला सचिवों से प्राप्त जानकारी के आधार पर भगुतान हेतु हर स्तर पर परिमंडल सचिव ने चर्चा कर भुगतान करवाने में सफलता अर्जित की है। आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि बीएसएनएल एम्पलॉइंज यूनियन – सीएचक्यू द्वारा भुगतान हेतु किए गए प्रयासों से सदस्यों को औपचारिक अनापचारिक चर्चाओं में अवगत करवाए।

डीपीसी : वाहनचालकों का प्रमोशन

वाहन चालकों के अपग्रेडेशन / प्रमोशन हेतु डीपीसी किए जाने हेतु परिमंडल यूनियन द्वारा परिमंडल प्रबंधन पर दबाव बनाया गया, कुछ साथियों के प्रमोशन आदेश जारी हुए। किन्तु कुछ प्रकरण फिर भी लंबित रहे। सर्कल ऑफिस को वांछित जानकारियां एसएसए/झोनल ऑफिस से प्राप्त न होने से प्रकरणों का निपटान नहीं हो सका है। ऐसे प्रकरणों हेतु प्रयास किए गए और आदेश जारी हुए।

WTP की समस्याएं

WTP की समस्याओं के निदान हेतु तीन पत्र लिखे गए। प्रकरण थे – रुल 8 अंतर्गत स्थानांतरण आदेश जारी करना, सर्कल ऑफिस से पत्रों, सूचनाओं का प्रेषण एवं WTP के स्टाफ का संबंधित एसएसए की ग्रेडेशन लिस्ट में समावेश।

टीटीए कन्फरमेशन सेक्युरिटी डिपॉजिट वापसी
उपर्युक्त मुद्राओं को लेकर कार्यवाही की गई। समस्या का निदान भी हुआ है।

SC/ST - JTO आदेश

कोर्ट में केस जीत चुके हमारे SC/ST के साथियों के JTO प्रमोशन आदेश परिमंडल यूनियन के हस्तक्षेप से जारी हुए।

सोसायटी बैंक आदि की रिकवरी – प्रेषण में देरी

कर्मचारियों के वेतन से बैंक/सोसायटी आदि के लोन की किश्तें काटने के बावजूद संबंधित बैंक/सोसायटी को यह राशि समयपर प्रेषित नहीं की जा रही है। इस देरी से बैंक/सोसायटी द्वारा लगाई गई पेनलटी का भुगतान कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से करना पड़ सकता है।

समस्या के निदान हेतु परिमंडल प्रबंधन से इस संबंध में पत्राचार किया गया है। प्रकरण हमारे सीचक्यू के ध्यान में भी लाया गया है।

उपर्युक्त के अलावा मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक एचआर एवं एडमिन से दो बार हमारे प्रतिनिधि मंडल ने

अरे बाबू ये पब्लिक है..... सब जानती है...

एनएफटीई के पास उपलब्धियों के नाम पर अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा 'शुच्य' इसीलिये तो बीएसएनएलईयू के लिये ओछे, घिनौने, गंदे, उलजलूल, सिर पैर विहीन शब्दों का उपयोग कर, बोनस नहीं मिला, ऐमआर खत्म, एलटीसी खत्म, लाखों का नुकसान (अर्थहीन केल्क्यूलेशन के साथ) आदि का एनएफटीई ढिंडोरा पीट रही है।

लेकिन एनएफटीई शायद यह भूल रही है कि हमारे सभी साथी सुविज्ञ हैं, हकीकत जानते हैं। वे सब जानते हैं कि अगर बीएसएनएल का निर्माण नहीं हुआ होता तो हमें सारी सुविधाएं हासिल रहती, पेंशन और नौकरी की सुरक्षितता रहती और पग पग पर संघर्ष के लिये बाध्य नहीं होना पड़ता ... बीएसएनएल के अस्तित्व को बचाने के लिये। और बीएसएनएल बनाने में एनएफटीई की षड्यंत्रकारी भूमिका से भी सब वाकिफ है।

एनएफटीई दुष्प्रचार कर कितना ही भ्रमित करने की कोशिश कर ले किन्तु वह यह नहीं जानती कि 'बाबू ये पब्लिक है ... सब जानती है।'

हर दुष्प्रचार पर हमारे साथी करेंगे प्रहार... एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन बनेगी सिर्फ बीएसएनएलईयू इस बार

रु 200/- की SIM से अब अन्य नेटवर्क के कॉल की सुविधा भी.....

बीएसएनएलईयू के प्रयासों से सभी नॉन- एकजीक्युटिव साथियों को रु 200/- की SIM दी गई थी। यूनियन इस पर अन्य नेटवर्क के कॉल की सुविधा की मांग भी लगातार कर रही थी। यूनियन के प्रयासों से इस सुविधा की उपलब्धता हेतु कार्पोरेट ऑफिस से प्रायोगिक तौर पर कुछ शर्तों के साथ आदेश जारी हो चुके हैं। आदेश के अनुसार इस SIM से अब रु 50/- के सर्कल में ऑफनेट कॉल (अन्य नेटवर्क के कॉल) प्रति माह किए जा सकेंगे और रु 200/- खत्म होने की स्थिति में टॉप अप भी डलवाया जा सकेगा.... बधाई....!

विभिन्न समस्याओं को निदान हेतु प्रस्तुत किया है। इस बुलेटिन में प्रतिनिधि मंडल द्वारा लिए गए प्रकरण अलग से प्रकाशित किए गए हैं।

परिमंडल सचिव द्वारा कुछ विशेष स्थानांतरण प्रमाण, व्यक्तिगत प्रकरण विशेष समस्याएं (छतरपुर प्रकरण), आदि के निदान हेतु सफल प्रयास किए गए हैं।

सभी समस्याओं के निदान हेतु हमारे परिमंडल अध्यक्ष, सभी जिला सचिव, सीईसी मेंबर्स का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। सामूहिक प्रयासों से हम दो-तीन प्रकरण को छोड़कर सभी समस्याओं के निदान में सफल हुए हैं। विभिन्न समस्याओं के निदान हेतु किया गया पत्राचार संचारलोक में प्रकाशित किया जा रहा है।

सीईसी नई दिल्ली में समस्याएं/सुझाव प्रस्तुत किए गए

नवंबर 2015 में नई दिल्ली में संपन्न सीईसी में परिमंडल की ओर से सुझाव/समस्याएं प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत किए गए सुझाव/समस्याएं इस बुलेटिन में प्रकाशित किए गए हैं।

नाकामी बेनकाब

जिस तरह से एनएफटीई के नेतागण छोटे छोटे मुद्राओं (छोटे छोटे इसलिये कि ये बड़ा तो कुछ सोच ही नहीं सकते) पर बीएसएनएलईयू को दोषारोपित कर रहे हैं उससे यह तो स्पष्ट है कि विगत तीन वर्षों से एनएफटीई को मान्यता प्राप्त होने के बावजूद वे कुछ भी करने में नाकाम ही रहे हैं। इसलिये वे सिर्फ बीएसएनएलईयू पर अपने झूठ के सहारे ओछे शब्दों से छिंटाकशी कर रहे हैं। ऐसा करके उनकी नाकामी को वे खुद बेनकाब कर रहे हैं। इसलिए अपने आपको बेनकाब करने के लिसे एक शुक्रिया के तो हकदार हैं वे तो शुक्रिया एनएफटीई।

जब एनएफटीई कुछ करने में सक्षम ही नहीं है तो उन्हें वोट क्यों दिया जाये सोचियेगा जरुर।

बीएसएनएल – कल आज और कल

बीएसएनएल को हर स्तर पर कमज़ोर करने की कोशिशें एक लंबे समय से की जाती रही है। हमारा अस्तित्व, बीएसएनएल का अस्तित्व, विनिवेश निजीकरण आदि। कई मुद्दे हमारे डर की वजह रहे हैं। किन्तु बीएसएनएल एम्प्लाईज यूनियन ने इस डर से न केवल हमें लड़ना सिखाया वरन् “सबके साथ बीएसएनएल का विकास” की अवधारणा के साथ सभी यूनियन्स् और एसोसिएशन्स् को “फोरम” के बेनर तले एकत्रित कर बीएसएनएल की वित्तीय जीवंतता सुनिश्चित की। लगातार संघर्ष करते हुए सरकार की नीतियों पर प्रहार करते हुए बीएसएनएल को हमने “टायटेनिक” नहीं बनने दिया। जी हां, बीएसएनएल अब डूबता जहाज नहीं है। संयुक्त संघर्ष में नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वहन करते हुए बीएसएनएल एम्प्लाईज यूनियन ने “मुस्कान के साथ सेवा” जैसा प्रोग्राम लांच कर कार्यसंस्कृति में बदलाव के आव्हान के साथ बीएसएनएल को आर्थिक उन्नयन की ओर अग्रसर किया है। हम आक्रामक तरीके से बीएसएनएल के विस्तार हेतु प्रतिबद्ध हैं। नतीजा हमारे सामने है... यह हमारी यूनियन की नीतियों का ही परिणाम है कि विगत वित्तीय वर्षों में हमने 672 करोड़ रुपयों का “ऑपरेटिंग प्राफिट” दर्ज किया है। जुलाई 2015 में बी एस एन एल ने अपने पूर्व परफॉरमेंस को दुगना करते हुए 16 लाख से अधिक मोबाईल कनेक्शन जोड़े हैं। जबकि इसी माह में एयरटेल ने सिर्फ 11.9 लाख और आयडिया ने मात्र 10.25 लाख कनेक्शन ही दिए। सितम्बर 2015 में हम 1 लाख से अधिक कनेक्शन निजी कंपनियों से MNP के माध्यम से छीनने में भी कामयाब हुए। जहां दिसंबर 2015 में हमने 17.5 लाख मोबाईल कनेक्शन देकर रिकार्ड स्थापित किया वहीं अपने ही बनाए रिकार्ड को ध्वस्त करते हुए जनवरी 2016 में 20.7 लाख कनेक्शन देकर हम शीर्ष पर रहे।

ऐसा कदापि नहीं है कि बी एस एन एल की प्रगति की गति केवल मोबाईल के क्षेत्र में ही है। फोरम के नेतृत्व में बनाई जा रही नीतियों के चलते लैंडलाईन क्षेत्र में भी सुधार परिलक्षित हो रहा है। लैंडलाईन कनेक्शन के ‘‘सरेंडर’’ पर अप्रत्याशित रूप से रोक लगी है। बी एस एन एल की वित्तीय स्थिति का ग्राफ भी सुधार दर्शा रहा है। 2013 – 14 वित्तीय वर्ष के रु. 691 करोड़ के ऑपरेशनल वित्तीय घाटे को पाटते हुए हमने 2014 – 15 में रु. 672 करोड़ के ऑपरेशनल प्रॉफिट के साथ कंपनी की बैलेंस शीट को सुशोभित किया है। विगत वित्तीय वर्ष में बीएसएनएल ने रु. 27242 करोड़ का राजस्व अर्जित करते हुए 4.6 प्रतिशत की वृद्धि भी प्रदर्शित की है। केपिटल

एक्सपेंडिचर हेतु 7700 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

हमारे सभी नॉन एकझीक्युटिव साथियों के सहयोग से दर्ज उपर्युक्त उपलब्धियां इन विपरित परिस्थितियों में असाधारण कही जा सकती हैं। संयुक्त आंदोलन, संयुक्त संघर्ष इन सुखद परिणामों की प्रशंसनीय वजह हैं।

बी एस एन एल को हम “टायटेनिक” बनने से रोकने में सफल हुए हैं। हमारा टायटेनिक अब उथल – पुथल भरे समंदर में भी शान से मस्ती में लहराता हुआ, हिचकोले खाता हुआ तैर रहा है। आखिर इस जहाज के कैप्टन हम ही तो हैं। धन्यवाद, कैप्टन पी अभिमन्यु।

कोशिशें, सहभागिता, सफलता

परिमंडल सचिव का कार्यभार 9.8.2015 को सर्वानुमति से मुझे सौंपने के बाद मैंने उसी दिन अपने संक्षिप्त उद्बोधन में “सामूहिक नेतृत्व” के कंसेप्ट की बात कही थी। मुझे इस बात की खुशी है कि विगत महीनों में हमने इसी अवधारणा के साथ कार्य किया और सीचक्यू, जेएसी, फोरम के आव्हान पर हुए प्रदर्शन, धरना और हड़ताल को सहजता एवं सुलभता से सफल बनाया।

पोस्टकार्ड अभियान

21 – 22 अप्रैल 2015 की हड़ताल पश्चात् 1.5.2015 को डॉट सचिव से विभिन्न मुद्दों के निवारण हेतु चर्चा हुई। किन्तु दिए गए आश्वासनों को लागू नहीं किया गया। इसलिए फोरम ने 10 से 22 अगस्त 2015 तक देशभर में पोस्टकार्ड अभियान चलाने का निर्णय लिया। इस अभियान के तहत बी एस एल के पुनरुत्थान के लिए फोरम द्वारा प्रस्तुत मांगों को तुरंत हल करने के अनुरोध के साथ माननीय संचार एवं सूचना मंत्री को पोस्टकार्ड भेजे गए। मध्यप्रदेश परिमंडल में भी इस अभियान में हमारे जिला सचिवों ने पूर्ण उत्साह प्रदर्शित किया। लगभग सभी एस एस ए से परिमंडल द्वारा कुल 4289 पोस्टकार्ड मंत्रीजी को प्रेषित किए गए।

2.9.2015 की हड़ताल

केन्द्रीय श्रम संगठनों के आव्हान पर सरकार की विभिन्न मजदूर – जन एवं देश विरोधी नीतियों के विरोध में 2.9.2015 की हड़ताल में परिमंडल ने जोरदार ढंग से शिरकत की। इस बार इस आम हड़ताल को मध्यप्रदेश परिमंडल में शानदार प्रतिसाद मिला। अधिकारियों की सहभागिता न होने के बावजूद हड़ताल में कर्मचारियों की बढ़चढ़ कर सहभागिता रही। परिमंडल के साथियों ने इस हड़ताल को अभूतपूर्व और अद्भूत सफलता प्रदत्त कर “संघर्षों का रास्ता सही रास्ता” की उकित को

यथार्थ में चरितार्थ कर मध्यप्रदेश बी एस एन एल के संघर्षशील नव दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया।

उपर्युक्त हड़ताल, पोस्टकार्ड अभियान के अलावा हुए अन्य प्रदर्शन एवं धरनों में भी हमारे जिला सचिवों, सी ई सी मेंबर्स, सक्रिय साथियों एवं सभी सदस्यों का अभूतपूर्व योगदान रहा। सभी का आभार।

पोस्टकार्ड अभियान, हड़ताल, धरना, प्रदर्शन आदि के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु पोस्टर, बैनर, पेम्पलेट आदि परंपरागत साधनों के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप, एस एम एस, हाईक, वेबसाइट आदि का भी परिमंडल द्वारा बखूबी उपयोग किया गया।

2.9.2015 को मध्यप्रदेश में हुई हड़ताल का हमारे महासचिव को पी अभिमन्यु ने अन्यत्र हुई सभाओं में भी विशेष उल्लेख किया। सीटू के लीडर्स, सीनियर कॉमरेड्स और हमारी परिमंडल टीम ने भी नए नेतृत्व की कार्यशैली की सराहना की।

संघर्ष के इस नवसंचारित जज्बे और उत्साह को बनाए रखने की हम सभी की जिम्मेदारी है।

संचारलोक एवं वेबसाइट

संचारलोक का नई कार्यकारिणी गठित होने के पश्चात् अभी तक कोई भी अंक प्रकाशित नहीं हुआ। मैं परिमंडल सचिव होने के नाते इस जिम्मेदारी का निर्वहन न होने की जिम्मेदारी लेता हूं मेरे साथ हुए हादसों के चलते यह संभव नहीं हो सका है—क्षमाप्रार्थी हूं।

वेबसाइट को सूचना का प्रबल स्त्रोत बनाने की कोशिश जारी है। सदस्यों एवं बीएसएनएल के हितों से सारोकार रखने वाली सभी सूचनाएं एवं जानकारियां प्रभावी ढंग से आप तक पहुंचाने के प्रयासों को पसंद किया जा रहा है। इसे और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का स्वागत है। वेरीफिकेशन पश्चात् वेबसाइट के कलेवर को भी परिवर्तित किया जाएगा। साथ ही विभिन्न महत्वपूर्ण कर्मचारियों से जुड़ी जानकारियों का भी इसमें समावेश होगा। अनुरोध है कि आपके लेटरपेड आदि में हमारी वेबसाइट www.bsnleump.com का उल्लेख हो यह सुनिश्चित करें।

यूनियन वेरीफिकेशन हम होंगे कामयाब

7 वें सदस्यता सत्यापन की घोषणा हो चुकी है। 10 मई 2016 को यूनियन सत्यापन हेतु चुनाव होंगे और 12 मई को बी एस एन एल एम्प्लाईज यूनियन की एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन की घोषणा होगी। जी हां, इस वेरीफिकेशन में हमारी यूनियन 70% से अधिक मत प्राप्त करेगी यह मेरा ही नहीं आम

सदस्यों का भी दृढ़ विश्वास है। बीएसएनएलईयू द्वारा सभी को साथ लेकर बीएसएनएल की जीवंतता हेतु किए गए सफल प्रयास और कर्मचारियों के हितार्थ और उनकी समस्याओं के निदान हेतु किए गए संघर्ष इस दृढ़ विश्वास का आधार है।

78.2 आईडीए विलय, नॉन – एकजीक्युटिवों के लिए नए पदनाम, टीटीएज के लिए एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट, आफिशिएटिंग जेटीओज के लिए नियमित प्रमोशन, संशोधित जेटीओ भर्ती नियम, अनुकंपा आधारित नियुक्तियां जैसी असंख्य उपलब्धियों के साथ एस सी / एस टी कर्मचारियों के जायज और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, एनॉमलीज का निदान, ग्रुप डी स्टेगनेशन का हल, पुत्र पुत्रियों को अनुकम्पा नियुक्तियां, पी एल आई, सीधे भर्ती कर्मचारियों के लिए पेंशन, प्रमोशन के अवसरों में सुधार और बी एस एन एल एम आर एस में परेशानियों को दूर करना जैसे असंख्य मुद्दों हेतु बीएसएनएलईयू प्रयास रहत है।

उपर्युक्त के अलावा विनिवेश, निजीकरण, टॉवर कंपनी, एमटीएनएल, बीएसएनएल का विलय, डेलाइटी कंसल्टेंट की रिपोर्ट का विरोध, बीएसएनएल का पुनरुत्थान आदि मुद्दों में भी बीएसएनएलईयू की नेतृत्वकारी और सफलतम भूमिका से सभी वाकिफ है।

आगामी दिनों में हमारी उपलब्धियों को “जन जन के मन तक पहुंचाने की हमारी छोटी सी किन्तु इमानदाराना कोशिश हमारी यूनियन को श्रेष्ठता के शिखर पर अवश्य ले जाएगी और 10 मई 2016 को होने वाले वेरीफिकेशन के परिणाम बीएसएनएल एम्प्लाईज यूनियन को एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा देंगे।

मुस्कान के साथ सेवा यानि SWAS प्रोग्राम का स्वागत

अहमदनगर सीईसी मे फोरम के आळान पर शुरू किए गए 100 दिवसीय मुस्कान के साथ सेवा यानि SWAS प्रोग्राम की सराहना की गई। साथ ही इस प्रोग्राम को पूर्णरूपेण सफल बनाने का संकल्प भी लिया गया। सीएचक्यू द्वारा SWAS की वजह से निर्मित उत्साह को हर हालत मे बनाए रखने का अनुरोध करते हुए आगामी वेरीफिकेशन के मद्देनजर SWAS की गति मे शिथिलता न आए इस बाबद भी विशेष रूप से सचेत किया गया।

हमारे सीएचक्यू की इस संबंध मे चिंता यह प्रदर्शित करती है कि हम बीएसएनएल के उन्नयन के प्रति कितने गंभीर हैं.....!

बीएसएनएलईयू बीएसएनएल की वित्तीय जीवंतता के लिए प्रतिबद्ध है। बीएसएनएलईयू जिंदाबाद.....

जरा सोचिए क्या होता गर.....

साथियों,

जैसा कि आप जानते हैं 1 अक्टूबर 2000 को एनएफटीई की बीएसएनएल बनवाने की विश्वासघाती भूमिका के साथ ही बीएसएनएल के निजीकरण की रुपरेखा तय हो चुकी थी, लेकिन बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन के निरंतर संघर्षों से बीएसएनएल को बचाया गया ! यदि बीएसएनएल का निजीकरण हो गया होता तो क्या होता.....आइये देखते हैं.....

★ यदि बीएसएनएल का निजीकरण हो जाता तो बीएसएनएल का मालिक कोई माल्या जैसा पूँजीपति होता और फिर हमारे साथ भी वह हो सकता था जो किंगफिशर एयर लाइन्स के कर्मचारियों के साथ माल्या ने किया ।

★ यदि बीएसएनएल का निजीकरण होता तो बीएसएनएल को खरीदने वाला मालिक बीएसएनएल के लाखों कर्मचारियों को नहीं रखता, निश्चित रूप से छटनी होती । हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं होता ।

★ यदि बीएसएनएल का निजीकरण हो जाता तो रिजर्वेशन पॉलिसी के अन्तर्गत एसटी/एससी कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलता क्योंकि किसी भी प्रायवेट कंपनी में रिजर्वेशन लागू नहीं है ।

★ यदि बीएसएनएल का निजीकरण हो जाता तो सरकारी श्रम कानून लागू नहीं होते और फिर हमारा हश्श भी वही होता जो निजी कम्पनियों के कर्मियों का होता यानि पग पग पर शोषण, छुट्टियां नहीं मिलती, एडवान्स नहीं मिलते, काम के घंटे अधिक होते,

एक प्री-मेच्योर्ड बेबी का जन्म.... जन्म के तुरंत बाद उसे दफनाने की कोशिशें और बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन की स्थापना के साथ एक मसीहा यूनियन की इस बेबी को जिंदगी देने की कहानी.....

निजीकरण के इरादों को नाकाम कर अपने और बीएसएनएल के भविष्य को सुरक्षित बनाना है.....

★ बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन की स्थापना 22 मार्च 2001 को विशाखापट्टनम मे संयुक्त अधिवेशन में हुई ।

★ छ: यूनियन जिनके मर्जर के बाद बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन का निर्माण हुआ था वे सभी यूनियन एनएफटीई (ओ पी गुप्ता सचिव प्रधान) की प्रोमेनेजमेंट पॉलिसी का विरोध करती रही है ।

तनख्वाह भी उम्मीद से बेहद कम होती , मेडिकल की सुविधा नहीं होती , प्रमोशन तो शायद एक सपना ही रह जाता....क्योंकि किसी भी प्रायवेट कंपनी में ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती है...मात्र शोषण होता है ।

★ यदि बीएसएनएल का निजीकरण होता तो देश में रोजगार के अवसर कम होते और जो भर्तियां बीएसएनएलईयू के प्रयास से हो रही है वह नहीं होती ।

★ यदि बीएसएनएल का निजीकरण होता तो प्रायवेट कंपनियां आपस में मिलकर कॉल रेट बढ़ाकर देश की जनता को बेतहाशा लूटती, शायद आप अभी तक भूले नहीं होंगे कि पहले 16 रुपये इनकमिंग कॉल के लिए जाते थे ।

★ बीएसएनएल के निजीकरण को बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन ने संघर्ष से रोका है और इस तरह हमने न केवल कर्मचारियों के भविष्य को महफूज बनाया है वरन् बीएसएनएल को जीवंत भी रखा है ।

शुक्रिया आपका जो आपने बीएसएनएल को बेच कर आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली यूनियन को दूसरे वेरिफिकेशन के बाद लगातार जीत से वंचित रखा है....अभी भी रखोगे... बीएसएनएल के और स्वयं के भविष्य के लिए....विश्वास है हमे आप पर....आपकी सूझबूझ पर.....!

तो भूलिएगा मत, 10 मई को वोट जरुर दीजिएगा.... बीएसएनएल बनाने वालों को करारी चोट जरुर दीजिएगा .. 9 नंबर के समक्ष मोबाईल पर हमें मोहर लगाना है..

★ एन एफ टी ई बीएसएनएल बनने के पहले एक ऐसी फेडरेशन थी जिसके अंतर्गत बहुत सी यूनियन कार्य करती थी ।

★ सरकार नीतिगत फैसलो पर सिर्फ एन एफ टी ई, (एफएनटीओ) एवं बी टी ई एफ से सहमति लेती थी ।

★ 1991 में रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर एन एफ टी ई(ओ पी गुप्ता) ने डेढ़ लाख पोस्टों को समाप्त करने के लिए सरकार को सहमति दे दी थी ।

- ★ जिसके बाद एन एफ टी ई में ओ पी गुप्ता सचिव प्रधान का देश भर में विरोध हुआ।
- ★ 1991 में एन एफ टी ई(ओ पी गुप्ता) की आलइण्डिया कॉन्फ्रेंस भोपाल में हुई।
- ★ भोपाल आलइण्डिया कॉन्फ्रेंस में ओ.पी. गुप्ता सचिव प्रधान पद हार गए।
- ★ भोपाल आलइण्डिया कॉन्फ्रेंस में कामरेड नम्बूदीरी को अध्यक्ष एवं कामरेड मोनी बोस को सचिव प्रधान एवं कामरेड एस आर नायक को सहायक महासचिव निर्वाचित घोषित किया गया।
- ★ उस वक्त सरकार ने कामरेड मोनी बोस को मान्यता नहीं दी, कहा ये गया की वो नियमित रूप से दूरसंचार विभाग के कर्मचारी नहीं है।
- ★ प्रकरण कोर्ट में गया और कामरेड मोनी बोस कोर्ट से जीते, लेकिन तब तक उनका कार्यकाल समाप्त हो चूका था।
- ★ जब प्रकरण कोर्ट में चला तो कामरेड नायक ने महासचिव के रूप में कार्य किया।
- ★ 1996 में एन एफ टी ई (गुप्ता) की आलइण्डिया कॉन्फ्रेंस त्रिवेंद्रम में हुई।
- ★ कामरेड नम्बूदीरी को महासचिव बनाया गया।
- ★ लेकिन कामरेड ओ पी गुप्ता ने पहले ही सरकार को खुद के महासचिव बनने की सूची सौंप दी थी। सरकार ने कामरेड ओ पी गुप्ता को महासचिव के रूप में मान्यता दे दी।
- ★ दूरसंचार मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद ऑल इंडिया टेलीकॉम एम्प्लाइज यूनियन क्लास 3 (नम्बूदीरी) के रूप में कामरेड नम्बूदीरी को महासचिव के रूप में मान्यता दे दी गई।
- ★ एक यूनियन के दो दावे प्रस्तुत होने पर जिस यूनियन के महासचिव कामरेड नम्बूदीरी थे उस यूनियन के नाम के आगे नम्बूदीरी जोड़ा गया।
- ★ एन एफ टी ई (ओ पी गुप्ता) लगातार सरकार को सहयोग कर रही थी इसलिए सरकार भी एन एफ टी ई को सहयोग करती थी।
- ★ जब बीएसएनएल बनाया जा रहा था तो कामरेड नम्बूदीरी ने समान विचार रखने वाली छह यूनियन को एक जुट करते हुए नेशनल एक्शन कमिटी का गठन किया और बीएसएनएल बनाने का पूरजोर विरोध किया।
- ★ उस वक्त यूनियन के साथ संख्या बल कम होने से और एन एफ टी ई द्वारा बीएसएनएल बनने की लिखित
- सहमति दिए जाने की वजह से कामरेड नम्बूदीरी संघर्ष के बावजूद बीएसएनएल बनने से नहीं रोक पाये।
- ★ ए जी फरग्यूसन कमिटी के रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार विभाग को 2001 में बीएसएनएल बनना था, लेकिन एन एफ टी ई सहित उस वक्त की मान्यता प्राप्त यूनियन के तैयार होने से एक साल पहले ही बीएसएनएल बना दिया गया।
- ★ इस तरह बीएसएनएल नाम की प्री-मेच्योर्ड बेबी का जन्म हो गया।
- ★ इस प्री-मेच्योर्ड बेबी की रक्षा करना एक बड़ी चुनौती थी।
- ★ क्योंकि बीएसएनएल को बेच देने के लिए कंपनी बनाइ गयी थी।
- ★ बीएसएनएल की रक्षा के लिए छः यूनियन का मर्जर हुआ और 22 मार्च 2001 को बीएसएनएल ई यू की स्थापना हुई।
- ★ बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन की स्थापना से ही बीएसएनएल ई यू बीएसएनएल की रक्षा कर रही है, और इस सुखद सत्य से आप और हम वाकिफ भी हैं। आप यह भी जानते हैं कि बीएसएनएलईयू ने किस तरह सभी को साथ लेकर एक प्री-मेच्योर्ड बेबी को जिंदा रखा है और मजबूत भी! वरना आपके अस्तित्व को गर्त मे ले जाने वाली एक यूनियन ने किस तरह इस बेबी को जन्म के तुरंत बाद खत्म करने की साजिश रखी थी यह भी सर्वविदित है!
- ★ इसी लिए 22 मार्च को बीएसएनएल ई यू का स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया जाता है।
- ★ बीएसएनएल ई यू के सदस्य होने पर हमें गर्व है और निःसंदेह आगामी वेरिफिकेशन मे हम सब मिल कर बीएसएनएलईयू को 60% से अधिक मतों से विजयी बनाएंगे....हमारे अपने और हमारे अपने बीएसएनएल के सुदृढ़ और सुखद भविष्य के लिए।

बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन, म.प्र. परिमंडल का नेतृत्व एक युवा, सशक्त, ऊर्जावान टीम के हाथों में है जो अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही है। म.प्र. परिमंडल में युवा एवं अनुभवी नेतृत्वकर्ताओं की अद्भुत सहभागिता है।

विगत कई वर्षों से हमारे और हमारे सदस्यों के बीच स्नेह और विश्वास का एक खूबसूरत रिश्ता है। आइए, 10.5.2016 को इस रिश्ते को अटूट बनाए।

BSNL EMPLOYEES UNION, M P CIRCLE, BHOPAL

आगामी वेरिफिकेशन हेतु परिमंडल पदाधिकारी निम्नानुसार जिलों के प्रभारी रहेंगे ।

वेरिफिकेशन के मद्देनजर जिला सचिवों के सहयोग एवं सुविधा हेतु परिमंडल के पदाधिकारियों को विभिन्न जिलों का प्रभार सौंपा गया है....जिला सचिव एवं परिमंडल पदाधिकारी वेरिफिकेशन से जुड़े विभिन्न कार्यों, सभाओं, प्रचार प्रसार आदि के सहज संचालन हेतु आपस मे संपर्क करें, यह निवेदन है...। विशेष परिस्थितियों में प्रभार परिवर्तन किया जा सकता है। परिमंडल सचिव को भी आपसी निर्णयों से अवगत करवाएं...! परिमंडल सचिव सभी जिलों के प्रभारी होंगे ।

1	COM-Prakash Sharma-Circle Secretary	Circle Secretary will tour all the SSA	9425076677
2	COM.BS Raghuvanshi-Circle President	Narsinghpur,Chhindwara,Damoh,,Seoni, Sagar	9424635999
3	COM.Jagdish Singh, CHQ VP	All SSA	9425801008
4	COM.H.S. Thakur-Vice President	Bhopal,Vidisha,Hoshangabad,Raisen, Rajgarh Beora	9425393197
5	COM-M.L. Choudhari-Vice President	Mandsaur,Ratlam,Ujjain,Indore	9425073477
6	COM-A.K.Jain- Vice President	Bhopal,CIVIL	9425372483
7	COM-P.K.Tawar-Vice President	Bhopal, Shajapur	9425301969
8	COM-OM Prakash Singh-Vice P.	Bhopal,WTP	9424410230
9	COM-Balendu Parsai-ACS	Betul, Dhar, Jhabua	9425023193
10	COM-Yogesh Sharma-ACS	Satna,Chhatarpur, Rewa	9425174140
11	COM-Lakhan Patel -ACS	Jabalpur,Sidhi,Mandla	9425360014
12	COM-Salamat Ali- ACS	Bhopal	9406532786
13	COM-Rakesh Yadav-ACS	Gwalior	8989415459
14	COM-S.N.S.Chouhan-Treasurer	Shahdol, Panna	9425836562
15	COM-Suneel Karan-Asstt.Treasurer	Bhopal	9424355559
16	COM-Manoj Chourasiya-ORG SEC.	Raisen,Vidisha	9406518900
17	COM-B.C.Raghuvanshi-ORG SEC.	Hoshangabad	9425493771
18	COM-R.S.Hora,Indore-ORG SEC.	Indore, Khargone	9424894248
19	COM--D.K.Meshram-ORG SEC.	Balaghat	8989053838
20	COM-Deepak Sharma-ORG SEC.	Khargone, Khandwa	9425333230
21	COM-R S Belgotra-ORG SEC.	Ujjain, Ratlam	9425093900
22	COM-Meena Chouradiya-ORG SEC.	Indore	9425076788
23	COM-S D Sharma-Auditor	Jabalpur	9425159342
24	COM-V M Parate	Mandsaur	9425360060
25	COM-P.L.Samire	Khandwa	9425928678
26	COM B S Davande	Chhindwara	9424636111
27	COM-Mool chand Soni	Sagar	9424451666
28	COM-R S Kushwaha	Ujjain	9425987087
29	COM-Satish Chandra Chouhan	Morena,Shivpuri	9425001768
30	COM-S.C.Shrivastav,Bhopal	Bhopal,Dewas, Any SSA on request	9425376533
31	COM-G.J.Shekhar,Gwalior	Gwalior Rajgarh Beora	9406969503
32	COM-D.S.Raghuvanshi,Gwalior	Gwalior,Morena,Shivpuri,Guna	9407217944
33	COM-Rashid Ali,Bhopal	Bhopal	9407528268
34	COM-Atiram Singh	Gwalior	9425337993
35	COM-G.P.Garg	Guna	9406509700
36	COM-Jagdish Soni	Indore	9424566877
37	COM-M K Uike	Bhopal	9425392441

स्वागतम् कॉ.पी.असोका बाबू

म.प्र. परिमंडल में सप्तम् यूनियन वेरिफिकेशन के दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉ.पी.असोका बाबू की जबलपुर, भोपाल एवं ग्वालियर में सभाओं का नेतृत्व कॉ. बी.एस. रघुवंशी, परिमंडल अध्यक्ष, कॉ. जगदीश सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कॉ.डी.एस.रघुवंशी, कॉ.एस.सी. श्रीवास्तव, वरिष्ठ मार्गदर्शक, कॉ.एच.एस.ठाकुर, परिमंडल उपाध्यक्ष, कॉ.आलोक नामदेव, परिमंडल सचिव (SNATTA) एवं कॉ.प्रकाश शर्मा, परिमंडल सचिव करेंगे।

List of Representatives of BSNLEU for VII Verification given to Circle Management

SL.NO.	DISTRICT	DISTRICT SECRETARY	MOBILE NO.
1	Balaghat	Com.G.R.Rale	9425448400
2	Betul	Com.B M Sonparate	9425003634
3	Bhopal Civil	Com.A.K.Jain	9425372483
4	Bhopal CO	Com.P.K.Tanwar	9425301969
5	Bhopal GMT	Com.Salamat Ali	9406532786
6	Bhopal WTP	Com.S.C.Khapre	9425649334
7	Chhatarpur	Com.Satyendra Jain	9425880808
8	Chhindwara	Com.B.S.Dawande	9424636111
9	Damoh	Com.Bhagwandas Kurmi	9406558999
10	Dewas	Com.B.L.Carpenter	9425074884
11	Dhar	Com.Kailash Chaudhari	9425312300
12	Guna	Com.G.P.Garg	9406509700
13	Gwalior	Com.D.K.Sharma	9425619780
14	Hoshangabad	Com.Mohan Malviya	9190234644
15	Indore	Com.Hemant Dubey	9424011665
16	Jabalpur	Com.Raghvendra Arjaria	9424300300
17	Jhabua	Com.Sharad Shastri	9425033330
18	Khandwa	Com.P.L.Samre	9425928678
19	Khargone	Com.Deepak Sharma	9425333230
20	Mandla	Com.Ravindra Baghel	8989152989
21	Mandsaur	Com.K.C.Sen	9425976777
22	Morena	Com.D.S.Bhadoria	9425418441
23	Narsinghpur	Com.B.S.Raghuvanshi	9424635999
24	Panna	Com.Jagdish Pathak	9425167766
25	Raisen	Com.Manoj Chaurasia	9406518900
26	Rajgarh Beora	Com.Arvind Vyas	9425037600
27	Ratlam	Com.Dinesh Untwal	9425364950
28	Rewa	Com.Pushpendra Singh	9425186833
29	Sagar	Com.D.S.Tekam	9425438530
30	Satna	Com.Yogesh Sharma	9425174140
31	Seoni	Com.J.D.Gajabhiye	8989483999
32	Shahdol	Com.R.P.Raut	9425809501
33	Shajapur	Com.Himanshu Dubey	9425034400
34	Shivpuri	Com.S.K.Agrawal	9425796600
35	Sidhi	Com.S.A.Khan	9425177786
36	Ujjain	Com.Manoj Sharma	9424811999
37	Vidisha	Com.R.K.Lariya	9425641400

परिमंडल की वेबसाईट www.bsnleump.com को निरंतर अपडेट किया जा रहा है एवं सदस्यों के हितार्थ विभिन्न जानकारियाँ वेबसाईट पर प्रसारित की जा रही हैं। विगत दिनों प्रसारित कुछ जानकारियों के अंश

आगामी दो-तीन माह के महत्वपूर्ण आयोजन....

अहमदनगर सीईसी मे निम्न महत्वपूर्ण दिवस गरिमामय तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया.

8 मार्च..... अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

22 मार्च..... बीएसएनएलईयू स्थापना दिवस

23 मार्च..... कॉमरेङ्स भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु शहादत दिवस

14 अप्रैल.... डॉ बाबासाहेब अंबेडकर जयंती

1 मई मजदूर दिवस (मई दिवस)

म.प्र. परिमंडल में महिला दिवस, स्थापना दिवस और शहादत दिवस पूर्ण गरिमा के साथ मनाए गए

आठवीं ऑल इण्डिया कॉन्फ्रेंस चेन्नई में

बीएसएनएल एम्पलाईज यूनियन की ऑल इण्डिया कॉन्फ्रेंस चेन्नई में संपन्न होगी. तमिलनाडु सर्कल ने सीएचक्यू से परामर्श कर ऑल इण्डिया कॉन्फ्रेंस चेन्नई मे 31.12.2016 से 3.1.2017 तक आयोजित करने का निर्णय लिया है।

रु.200/- प्रीपेड सिम पर अन्य कंपनियों के कॉल (ऑफनेट कॉल्स) की सुविधा दी जाये

नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को दी गई रु.200/- की प्रीपेड सिम पर अन्य कंपनियों के कॉल करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 14 मई 2015 को संपन्न 32वीं नेशनल कॉउंसिल मीटिंग में विस्तृत चर्चा की गई थी। इस मीटिंग में यह भी तय किया गया था कि प्रायोगिक तौर पर छह माह हेतु कर्नाटक सर्कल ऑफनेट कॉल की सुविधा रु.200/- के सिम कार्ड पर प्रदान कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ! इस रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्यवाही की जाएगी, किन्तु यह रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित है। इसके अलावा कॉर्पोरेट ऑफिस में कई उच्च अधिकारीयों से भी कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। किन्तु सकारात्मक निर्णय का इंतजार है। "सर्विस विथ ए स्माइल" के तहत नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी मार्केटिंग गतिविधियों मे पूर्ण उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में अन्य नेटवर्क पर कॉल करने की सुविधा नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मियों को शीघ्र देने की मांग डायरेक्टर (एच आर) को 8.2.2016 को बीएसएनएलईयू के महासचिव को पी अभिमन्यु द्वारा लिखे पत्र में की गई है। **आदेश हो गए हैं।**

एस सी एस टी रिजर्वेशन का अनुपालन

एस सी एस टी रिजर्वेशन हेतु डीओपीएंडटी के आदेश के बीएसएनएल में अनुपालन हेतु बीएसएनएल ईयू सतत् प्रयासरत है। इस हेतु गठित कमिटी द्वारा तय सीमा में आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने पर हमारे सीएचक्यू ने रोष व्यक्त करते हुए डायरेक्टर (एच आर) को पत्र प्रेषित किया है।

JTO LICE 2013 ...अतिरिक्त अंक की मांग

JTO LICE 2013 की परीक्षा में गलत प्रश्नों के एवज में अतिरिक्त अंक देने की मांग BSNLEU द्वारा लगातार की जा रही है। अपने प्रयासों की इसी कड़ी में हमारे महासचिव कॉ.पी अभिमन्यु ने डायरेक्टर (एच आर) से पुनः मुलाकात कर सभी सर्कल्स् को उक्त एक्झाम मे गलत प्रश्नों के लिए अतिरिक्त अंक देने हेतु उचित निर्देश जारी करने की मांग की है। डायरेक्टर (एच आर) श्रीमती सुजाता रे ने GM (Rectt) को तत्काल इस सम्बन्ध मे पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। बी एस एन एल ई यू के प्रयासों को शीघ्र सफलता मिलेगी, हमें विश्वास है।

मुनाफा नहीं तो वेतन में वृद्धि भी नहीं - सी एम डी का बयान

बी एस एन एल के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर ने बंगलौर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सन् 2017 बी एस एन एल के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में जाना जाएगा क्योंकि तीसरी पी आर सी के माध्यम से बी एस एन एल के कर्मचारी अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण इस वर्ष में ही होना है। किन्तु मैं स्पष्ट कर दूँ कि बीएसएनएल लाभ की स्थिति में न होने पर किसी प्रकार की वेतन बढ़ोतरी नहीं होगी।

शतप्रतिशत हड्डताल होगी - बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन की कड़ी प्रतिक्रिया

बी एस एन एल एम्प्लाइज यूनियन ने सीएमडी के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि बीएसएनएल के सी एम डी कह चुके हैं कि समय पर इक्वीपमेंट न मिलने से हम बस चूँगे थे। माननीय संचार मंत्री श्री. रविशंकर प्रसाद भी पार्लियामेंट में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि पिछली सरकार ने बी एस एन एल का विकास विगत दस वर्षों से अवरुद्ध कर रखा था। इससे यह स्पष्ट है कि बी एस एल की घाटे की स्थिति के लिए कर्मचारी नहीं वरन् सरकार जिम्मेदार है। कर्मचारियों द्वारा पूर्व में कस्टमर डिलाइट इयर एवं वर्तमान में सर्विस विथ ए स्माइल कार्यक्रमों के द्वारा बी एस एल के आर्थिक उन्नयन के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व सरकार की गलत नीतियों की वजह से उपजी स्थितियों के लिए प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को प्रताड़ित करना पूर्ण रूपेण अनुचित होगा। बी एस एल के सभी एकजीक्यूटिव एवं नॉन एकजीक्यूटिव को 1.1.2017 से नया वेतनमान देना ही होगा। वरना बी एस एल में 100% हड्डताल होगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी बी एस एल प्रबंधन की होगी।

जे टी ओ रिजल्ट रिव्यू ... कोशिश निरंतर जारी

दिनांक 13.1.2016 को हमारे मा. महासचिव कॉ पी अभिमन्यु ने कार्पोरेट ऑफिस मे श्री डी चक्रबोर्टी, जीएम रिक्रूटमेंट से मिल कर 2.6.2013 को संपन्न जेटीओ एकझाम मे गलत प्रश्नो के लिए अंक देने एवं रिजल्ट रिव्यू करने हेतु यथोचित निर्देश जारी करने की पुनः मांग की। पूर्व मे यह प्रकरण डायरेक्टर (एच आर) के ध्यान मे भी लाया जा चुका है। इस संबंध मे परिमंडल सचिव कॉ प्रकाश शर्मा ने भी सीजीएम को पत्र लिखा है। चर्चा उपरांत जीएम रिक्रूटमेंट ने परिमंडल प्रबंधन को यथोचित निर्देश जारी करने बाबद आश्वासित किया है। रिजल्ट रिव्यू हेतु बीएसएनएलईयू के प्रयास निरंतर जारी है।

मुख्य महाप्रबंधक से दिनांक 17.11.2015 को चर्चा (सतना, जबलपुर, टीटीए आदि मुद्दों पर विशेष रूप से)

सचिव मंडल की बैठक के उपरान्त परिमंडल सचिव कामरेड प्रकाश शर्मा ,सहायक परिमंडल सचिव बी.के. परसाई ,परिमंडल उपाध्यक्ष ए .के .जैन ने मुख्य महाप्रबंधक डा.गणेश चंद्र पांडे जी से मुलाकात की और जबलपुर प्रबंधन के उदासीन रवैये के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की .सतना प्रबंधन के सम्बन्ध में भी चर्चा की गयी .इस सम्बन्ध में दोनों एस एस ए हेड से चर्चा और उचित मार्गदर्शन देने का भरोसा दिलाया .अनुकम्पा नियुक्ति रोक के सम्बन्ध में उन्होंने आशवाशन दिया कि जल्द ही कार्यवाही कर रोक हटा ली जाएगी ,टी टी ए के सम्बन्ध में उन्होंने कोर्ट के आदेशों को मानने की बात कही .और कॉर्पोरेट ऑफिस के आदेशों के दिशा निर्देशों का पालन करने की बाध्यता बतलाई ..धार ,पीतमपुर की सामान की समस्याओं का जल्द ही हल करने का भरोसा दिलाया . मेडिकल अदालत अब 8 दिसम्बर 20 15 को होगी .चर्चा के बाद फोरम की बैठक हुई .

जिला यूनियनो के एवं अन्य समाचार

संचार लोक के इस अंक मे स्थानाभाव के कारण जिला, परिमंडल और राष्ट्रीय स्तर पर किए गये आंदोलन, सेमीनार, अधिवेशन, राष्ट्रीय कार्यक्रमों का अनुपालन, हमारे साथियों द्वारा बीएसएनएल के उन्नयन हेतु किए जा रहे प्रयास, मुस्कान के साथ सेवा आदि से संबंधित समाचार प्रकाशित नहीं किए जा रहे हैं ! क्षमस्व हूँ....यह सब कुछ और फोटोज आगामी अंक मे समायोजित किए जाएंगे !

स्वागतम SNATTA...हम साथ साथ हैं

विगत वेरिफिकेशन में SNATTA हमारे साथ नहीं था किन्तु इस वेरिफिकेशन में SNATTA से समझौता हो गया है और अब SNATTA के लगभग 11000 से अधिक सदस्य BSNLEU के पक्ष में वोट करेंगे।

इस समझौते से NFTE के खेमे में बौखलाहट है, हताशा है, निराशा है। यहां यह स्पष्ट करना मौजूद होगा कि विगत वेरिफिकेशन में BSNLEU को 48.6% वोट मिले थे और NFTE को मात्र 30.28%। यानि हम 50% से मात्र 1.4% वोट की दूरी पर थे। जाहिर है, इस बार सभी ने बीएसएनएल को एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा देने का मन बना लिया है और SNATTA का BSNLEU से समझौता इस स्थिति को और अधिक पुख्ता बनाता है।

हम SNATTA के परिमंडल सचिव कॉ आलोक नामदेव और परिमंडल अध्यक्ष कॉ मयंक चतुर्वेदी, परिमंडल के अन्य पदाधिकारी एवं सभी सम्माननीय सदस्यों का स्वागत करते हैं....दिल से। SNATTA के लगभग लगभग सभी सदस्य इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, सुलझी हुई सौच के धनी हैं, युवा हैं, जोशीले हैं, उत्साह से ओतप्रोत हैं। निःसंदेह इनके “साथ” से बीएसएनएलइयू के “हाथ” और अधिक मजबूत होंगे। वैसे तो SNATTA के सभी लीडर्स और सदस्य बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन द्वारा राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर सभी टीटीए साथियों के हितार्थ किए गए कार्यों से वाकिफ हैं ही किन्तु हम पुनः उन्हें विश्वास दिलाना चाहेंगे कि बीएसएनएलइयू सदैव SNATTA के साथ बने इस नव-रिश्ते की प्रगाढ़ता के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगी। जिनसे उनका पूर्व में एलायंस था उन्होंने एलायंस धर्म का निर्वहन न करते हुए कई जिलों में SNATTA को कौंसिल में उनके स्थान से वंचित रखा था किन्तु बीएसएनएलइयू अपने एलायंस धर्म का पूर्ण सम्मान करेगी....विश्वास रखिएगा।

स्टेगेनेशन का मुद्दा

- ★ 65% साथियों को वार्षिक इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है।
- ★ इस बात से बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन वाकिफ थी। बीएसएनएलइयू ने ओपन एंडेड वेतनमान की मांग की थी। प्रबंधन का कहना था कि पेंशन अंशदान सिर्फ अधिकतम पर ही दिया जा सकता है अतः यह संभव नहीं है।
- ★ प्रबंधन 15 स्पैन के वेतनमान पर अंडिंग था... बीएसएनएलइयू ने 21/22 स्पैन के वेतनमान हासिल किए।

यदि 15 स्पैन के वेतनमान होते तो आज सभी कर्मी स्टैगेनेशन की स्थिति में आ जाते।

★ पेशन अंशदान की राशि में इजाफा न हो इस हेतु 21/22 स्पैन से ज्यादा के लिए प्रबंधन सहमत नहीं हुआ।

★ हम इसमें सुधार हेतु संघर्ष के लिए तैयार थे किन्तु एनएफटीई ने हस्ताक्षर अभियान चला कर नए वेतनमान की घोषणा में शीघ्रता की मांग कर प्रबंधन को अपनी मौन स्वीकृति दी। और वही एनएफटीई आज हमारे ग्रुप डी साथियों को मनगढ़त आंकड़े पेश कर उनके नुकसान का हवाला देकर घड़ियाली आंसू बहा रही है।

यहां यह याद दिलाना जरुरी है कि यह वही एनएफटीई है जिसने बीएसएनएल बनने के बाद ग्रुप डी साथियों के लिए रु. 3400/- न्यूनतम वेतन का समझौता किया था। किन्तु बीएसएनएलइयू और अन्य यूनियनों के संघर्ष के कारण न्यूनतम वेतन रु. 400/- किया जा सका। यदि एनएफटीई भी तरधात नहीं करती तो न्यूनतम वेतन रु. 4400/- होता। रु. 400/- कम वेतन की वजह से अगले वेतनमान पर भी इसका दुष्प्रभाव हुआ।

★ 78.2% आधारित नए संशोधित वेतन की वजह से स्टेगेनेशन की स्थिति ज्यादा निर्मित हुई।

★ अपने प्रयासों के अंतर्गत बीएसएनएलइयू ने वेतनमान मर्ज करने की भी मांग की किन्तु प्रबंधन ने असमर्थता व्यक्त की।

★ छठे वेतन आयोग और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुरूप अधिकतम पर पहुंचने पर उच्च पे बैंड में एक इंक्रीमेंट का लाभ देने की मांग को बीएसएनएल में लागू करने का अनुरोध भी किया गया।

★ 27.11.2014 की हड़ताल में भी यह मुद्दा प्रथम वरियता पर रहा।

★ अभी हाल ही में 11.1.2016 की बैठक में प्रत्येक वर्ष स्टैगेनेशन इंक्रीमेंट देने की मांग पर प्रबंधन सहमत हुआ है और इसे डॉट/डीपीई को रेफर करने की सहमति दी है।

किन्तु BSNLEU पर आरोप लगाने वाली NFTE से यह पूछा जाना चाहिए कि इस मुद्दे के निराकरण के लिए NFTE ने क्या प्रयास किए। मान्यता तो उन्हें भी थी। NFTE सदैव आरोप लगाने में ही मशगूल रहती है जबकि BSNLEU समस्या के समाधान के लिए सदैव प्रयासरत। सिर्फ आरोप लगाना और समस्या के निदान से पल्ला झाड़ लेना NFTE की पुरानी चारित्रिक विशेषता है।

**बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियनसी एच क्यू द्वारा
विगत दिनों किये गए विभिन्न प्रयासों पर एक नजर...**

★ बैंक लोन हेतु विभिन्न बैंकों से न्यू MOUs (समझौता पत्रक) हेतु कॉ.पी अभिमन्यु ने कॉर्पोरेट ऑफिस में GM (T & BFCI) से चर्चा की। प्रबंधन द्वारा बताया गया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिंडिकेट बैंक, एच डी एफ सी बैंक, जे एंड के बैंक के साथ शीघ्र ही समझौता पत्रक पर हस्ताक्षर हो जावेंगे। केनरा बैंक से भी प्रयास जारी है। यूनियन बैंक की कड़ी शर्त के चलते समझौता होने की सम्भावनाएँ क्षीण हैं।

★ रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरें कम की गयी हैं अतः बीएसएनएल कर्मियों को भी निम्न दरों पर लोन मिले यह सुनिश्चित करने का अनुरोध भी हमारे महासचिव ने संबंधित जीएम से किया है।

JTO LICE 2013...

★ गलत प्रश्नों के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाने की मांग को लेकर निरंतर प्रयास किये गए हैं... जारी हैं।

★ GM(पर्सोनल)से अनुरोध किया गया है कि माननीय जोधपुर CAT के स्टे को खारिज करने की कार्यवाही करने हेतु उचित कदम उठाएँ एवं JTO(T) LICE आयोजित करें।

कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा जारी

★ एग्जामिनेशन केलेंडर में TM LDCE एवं TTA LDCE का उल्लेख नहीं है। इसे शामिल करने हेतु कॉ.पी अभिमन्यु ने पत्र लिखा है।

★ टी टी ए केडर को सर्कल केडर घोषित किये जाने से पदोन्नति प्राप्त TTAs को ट्रेनिंग पश्चात दूरस्थ स्टेशन पर पदस्थ किया जा रहा है। BSNLEU ने TTA को सर्कल केडर घोषित किये जाने का विरोध करते हुए डायरेक्टर (एचआर) से मांग की है कि सभी TTAs को प्रशिक्षण

उपरान्त उनके पेरेंट एस ए में ही पोस्ट किया जाए।

★ JTO (LICE) एवं JAO एग्जाम दो अलग अलग तिथियों पर होंगे।

★ कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा JTO (T) 50% LICE एवं JAO 40% LICE परीक्षा 22.5.2016 को आयोजित किये जाने के निर्देश सभी सी जी एम को दिए गए हैं।

★ यदि ये दोनों परीक्षाएँ एक ही दिन ली जाती हैं तो दोनों परीक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को किसी एक एग्जाम से वंचित होना पड़ेगा। अतः बीएसएनएलईयू महासचिव ने डायरेक्टर (एच आर) को पत्र लिखकर ये दोनों परीक्षाएँ अलग अलग दिन आयोजित करने का अनुरोध किया है।

मेडिकल सुविधाओं में सुधार ... प्रथम मीटिंग

उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं में सुधार—सुझाव हेतु गठित कमिटी की प्रथम बैठक में प्रबंधन पक्ष के समक्ष कॉ.पी अभिमन्यु GS,BSNLEU ने CGHS दरें बेहद कम होने एवं बिल भुगतान में देरी होने से अच्छे हॉस्पिटल्स की BSNL से जुड़ने में अरुचि (एम्पेनलमेंट) की ओर ध्यान आकर्षित किया। BSNLMRS के तहत कम राशि के बिल स्वीकृत होने से कर्मचारियों द्वारा एक बड़ी राशि स्वयं की ओर से खर्च होने पर उन्होंने चिंता व्यक्त की एवं BSNLMRS में सुधार हेतु सुझाव दिए जिस पर विस्तृत चर्चा पश्चात् निम्न निर्णय लिए गए।

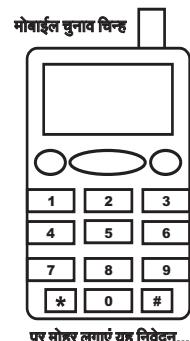
1) अन्य पी एस यू, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भेल आदि में प्रचलित मेडिकल सुविधाओं का अध्ययन किया जाएगा।

2) मेडिकल सिस्टम की BSNL में सार्थकता पर विचार किया जाएगा।

3) कॉर्पोरेट ऑफिस मेडिकल बिलों के त्वरित निपटान हेतु सभी सर्कल्स को निर्देशित करेगा।

9
मतपत्र में क्रमांक

**आपका हित
BSNLEU
के साथ है
सुरक्षित**



अहमद नगर में तीन दिवसीय विस्तारित सीईसी की शानदार शुरुआत

अहमद नगर में 19/02/2016 को कॉ.बलबीर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय ध्वज एवम् कॉ.पी अभिमन्यु द्वारा यूनियन ध्वज फहराने के साथ ही बीएसएनएलईयू की विस्तारित राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक की शानदार शुरुआत हुई। कॉ नलावडे, सर्कल सेक्रेटरी महाराष्ट्र सर्कल द्वारा सभी का स्वागत किया गया। सीटू महाराष्ट्र के जी एस डॉ कराडे द्वारा शुभारंभ पश्चात कॉ.नम्बूदिरी, संरक्षक ने संबोधित किया। तत्पश्चात् महासचिव कॉ.पी अभिमन्यु ने अपने संबोधन में विगत तीन वर्षों में नॉन एग्ज़ीक्यूटिव कर्मियों की समस्याएं एवं यूनियन द्वारा निदान हेतु उठाए गए कदम, बीएसएनएल की जीवंतता एवं बीएसएनएलईयू द्वारा किये गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

हमारे परिमंडल से कॉ.बी एस रघुवंशी, परिमंडल अध्यक्ष एवम् कॉ.जगदीश सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व में 30 साथियों ने सीईसी में शिरकत की। सीईसी में परिमंडल सचिव के रूप में कॉ.बी एस रघुवंशी एवम् सह परिमंडल सचिव कॉ योगेश शर्मा ने बेहद प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखते हुए संबोधित किया। कॉ रघुवंशी ने परिमंडल में संगठनात्मक स्थिति, चुनिंदा समस्याएं और आगामी वेरिफिकेशन हेतु हमारी रणनीति पर प्रकाश डाला। हमारे दोनों लीडर्स के वक्तव्यों को काफी सराहा गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉ.जगदीश सिंह ने भी सीईसी में अपने विचार रखे। हमारे सभी जिला सचिव बेहद अनुशासित तरीके एवं गंभीरता के साथ अपनी भूमिका का सीईसी में निर्वहन किया, उनका आभार।

महाराष्ट्र परिमंडल ने सीईसी की उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की। रीसेप्शन कमिटी, अहमदनगर की मध्य प्रदेश परिमंडल भूरि भूरि प्रशंसा करता है।

अहमदनगर सीईसी सफलता पूर्वक संपन्न

21.2.2016 को विस्तारित सीईसी सफलता पूर्वक संपन्न हुई। तीन दिवसीय सीईसी में 7 वें सदस्यता सत्यापन, मुस्कान के साथ सेवा यानि SWAS, नॉन एकझीक्यूटिव के लंबित मुद्दे आदि विषयों पर गहन चर्चा हुई। सीईसी मेंबर्स एवं जिला सचिवों ने गंभीरता से चर्चाओं में हिस्सा लिया। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए एवं विभिन्न प्रस्ताव भी पारित किए गए। महाराष्ट्र परिमंडल द्वारा की गई बेहतरीन व्यवस्थाओं की सभी ने सराहना की। परिमंडल अध्यक्ष कॉ बी एस रघुवंशी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉ जगदीश सिंह ने मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया। हमारे परिमंडल से कुल 29 डेलीगेट्स शामिल हुए। 90% + उपस्थिति की श्रेणी में हमारे परिमंडल को रखा गया। इस हेतु अहमदनगर जाने वाले सभी साथियों का परिमंडल की ओर से दिली आभार.....!

CITU ने सरकार की PSUs की रणनीतिक विक्रय योजना की भत्सना की - देशव्यापी विरोध का अनुरोध भी

देश के प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक "हिन्दू" (5.2.2016) के अनुसार सरकार की देश के सर्वाधिक प्रभावशाली एवं मुनाफा देने वाले PSUs के रणनीतिक विक्रय एवं अन्य PSUs में विनिवेश की योजना है। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार "ग्लोबल प्लेयर्स" को लाभ पहुँचाने के लिए देश की आर्थिक रूप से सक्षम कंपनियों को गिरते हुए स्टॉक मार्केट के चलते "औने पौने दामों में" निजी क्षेत्र को सौंपना चाहती है। यदि इस खबर में आंशिक सच्चाई भी है तो यह कदम राष्ट्र एवं आमजनों के हितों के मद्देनज़र घातक साबित होगा। रिपोर्ट के अनुसार इंजीनियरिंग क्षेत्र में वैशिक रूतबा रखने वाली BHEL, मुनाफे में चल रहे ऑर्डर PSUs: ONGC, HPCL, BPCL, IOC, डिफेन्स सेक्टर PSUs : BEML, HAL आदि को रणनीतिक विक्रय हेतु सूचीबद्ध कर लिया गया है। सरकार भले ही आर्थिक प्रगति के बड़े बड़े दावे कर ले लेकिन सरकार का यह रुख देश की जर्जर होती आर्थिक स्थिति को ही प्रदर्शित करता है। किन्तु देश की जनता सरकार के इस रवैये के प्रति मूकदर्शक बनकर नहीं रहेगी। CITU ने अपनी प्रेस रिलीज़ में सरकार के देश को गिरवी रखने के इस कदम की कड़ी भत्सना करते हुए यह मांग की है कि देश के आर्थिक तंत्र को मजबूती प्रदत्त करने वाली कंपनियों के विक्रय एवं विनिवेश की घातक योजना पर सरकार लगाम कसे।

नवम्बर 2015 में नई दिल्ली में सम्पन्न राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में परिमंडल सचिव को. प्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत समस्याएँ एवं सुझाव

To

**Com. P. Abhimanyu,
General Secretary,
BSNL Employees Union,
CHQ, New Delhi.**

Sub : Regarding , PROBLEMS, RESOLUTIONS & PROPOSALS .

Res Comrade,

I am submitting the following problems, proposals, resolutions etc in the CEC being held on 24th & 25th instant at New Delhi.

ORGANISATIONAL ISSUES :

Circle conference was held in M P Circle on 8.11.2015 & 9.11.2015 wherein a set of New Office Bearers was elected unanimously & it took merely 8 to 10 minutes to complete the process. Our Circle Executive Body comprises a good number of youngsters while the experienced leaders are also the part of the body in suitable no. to steer the organization in right direction. Circle Executive is emphasizing on the democratic functioning and as per schedule conference is being held in every SSAs barring a few one.

Membership: Total no. of Non-Executives is 6600+ in our circle. The break up is

BSNLEU....3643 NFTE....2195 FNTO....132 BTEU....32 OTHERS...23

Observance of Calls: We observe all the calls given by CHQ, JAC & Forum. Also follows the CHQ instructions to celebrate various programs. Postcard campaign was successfully implemented. Strike of Sept 2, 2015 was a big success which was hailed by the senior Comrades, CITU & CHQ. NFTE was convinced to join ,.Sabotage by them marred the total success at some places. We have been successful in instilling enthusiasm and zeal in members and promoting their mindset for the struggle through social media viz whats app, hike, face book, sms etc.. Demonstrations & Dharnas were successfully organized.

Council / Works Committee / CCWF / AIBDPA : Council meetings are being held. In many SSAs NFTE is reluctant in submission of agenda at some places, as reported. Management is being pressurized to hold Works Committee meetings at all places. Contract & Casual Workers Federation is not active in all SSAs. A lot is to be done to strengthen CCWF. Wherever the conference is held, We utilize the opportunity for formation of AIBDPA. We will overcome the lethargy.

Functioning of Forum: We enjoy cordial relationship with the Forum Constituents.

Meetings of Forum are held before the agitation starts to draw the strategy.. In MP, CGMT is convening Joint Meetings before arriving at any major decision , policy matter. Meetings are held by CGMT with Forum twice a month.

Programs for Development: Joint efforts are being made as per CHQ & Forum decisions for development & revival of BSNL. As per Forum call Giant Rallies were held in almost all SSAs to publicize our products, especially **Free Roaming and Free Night Calling**. In big cities our CGMT leaded the rallies with Forum Leaders. Ladies and Gents both participated with enthusiasm. Melas are being organized. SIM sell activities are boosted up. Implementation of operation Samudra Manthan is in full swing. COW BTS were used for the first time during One Day International Cricket Match between India & South Africa for better & uninterrupted coverage. CSC Training programs are being organized for better customer care wherein Forum Leaders are invited as Key-Note Speakers. To boost the morale of the employees Medical Adalat Concept is introduced in MP by CGMT

Proposals, Problems & Suggestions : In this CEC we submit the following.

1 The stagnation issue of Group D : Redressal is must before we go for Verification.

2 78.2% Benefit for Pensioners : Retired Members are eagerly waiting.

3.Mediclaim or Cashless Hospitalization : It is suggested to offer mediclaim policy to the workers to reimburse the medical expenses being incurred by them in excess of the CGHS rates. A thorough indepth study by experts of the field be made and if it is viable both for the staff and BSNL, go for it. If not, full cashless medical facility is the need of the hour as the

sufferers are looted by the hospital authorities. A big amount of the medical bill after hospitalization is being borne by the staff. This should be looked into seriously.

4 Increase in Insurance amt : It is suggested to demand increase in Insurance amount from 1 lac to 3 lacs by increasing premium of Rs105/- pm suitably.

5. Abolish Zonal Concept: MP is the only state wherein zonal concept is introduced before submission of Delloitte Consultant recommendations. This has increased hardships for staff and hampered routine function. Claims are being delayed. It is nothing but a stumbling block in smooth functioning of the various developmental, maintenance activities and hampering the work. **It is requested to abolish the system and revert back to the normal procedures.**

6. Promotional Prospects for Sports Quota Recruits : As per new TTA & JTO RR the recruits in sports quota , the Junior Sports Assistants are not eligible for the departmental promotional exams as the eligibility is linked with the scale. As such though the JSA possess the requisite qualification, they can't appear in the exam. Some amendment is requested to remove the blocks in promotional avenues and to promote the sports in BSNL. Also abolish negative marking system in departmental exams.

7 Release of Funds : Many of our Comrades have taken loans from Banks, Co-operative Societies and other financial institutes. After introduction of ERP, the installments deducted against the loan are not being sent to the concerned bank or society within the stipulated date resulting in additional burden of interest due to delayed payment. Circle authorities have informed that the funds are not received in time from corporate office. Kindly do the needful.

8 Software Cell: We have a good no of the best engineers still we are outsourcing the maintenance of computers and spending huge amount on purchase of various softwares from the MNCs. It is suggested to form a Software Cell wherein our own engineers be posted . They should research on creation of software as per our requirement. A separate set of engineers can mange maintenance activities of the hardware. Money saved is money earned, this will save a big amount of BSNL. Possibilities of utilization of our own brain & talent be explored in various fields to curb the outsourcing.

9 Training Program : Training be given to our staff for BB maintenance and Provisioning, maintenance of power plants etc.

10 TTA Exam Result, Release of Funds I am very much thankful to you in this CEC for continuously pursuing the TTA Result Discrepancy issue. CGMT has denied to take action by citing court orders. Now all hopes are pinned up on CHQ & CO.

I on behalf of my colleagues also express my gratitude for endeavoring constantly for release of funds for GPF and Festival advances.

11 Second Saturday : Banks have taken decision of closure on two Saturdays in a month. Members have requested to raise the issue of closure on Second Saturday in all BSNL units too. Kindly take up suitably.

12.Timings of CSCs : To render better services to the customers a concept of 8 am to 8 pm working is introduced in BSNL. We do not oppose the idea , but it has been experienced that before 9 am and after 7 pm the customer entry in CSCs etc is almost zero. This should be re pondered over and to curb the un-useful expenses on electricity etc , the timings may be changed.

In this CEC M P Comrades also salute to Kerala Comrades for showing the courage and their struggle for the betterment of workers . We also give our consent for renovation of Dada Ghosh Bhavan. And also, K G Bose Memorial and Educational Trust be made more stronger financially to expand its activities, We feel.

We are thankful to CHQ and Forum for their action to oppose formation of Tower Company, Merger of MTNL BSNL, Designation Change, outsourcing, continuous struggle against privatization and disinvestment & so on. Your efforts for upliftment and revival of BSNL are highly appreciated. It is BSNLEU , due to which the BSNL still enjoy the status of PSU and thanks to you for heading such A Giant Organization. M P Circle hails CHQ for their relentless efforts.

We wish all success for the CEC.

Submitted in CEC New Delhi by: **Prakash Sharma**, Circle Secretary, M.P. Circle

इसी सीईसी में कॉ. प्रकाश शर्मा द्वारा अपने उद्बोधन में डॉ. बाबा साहेब अंबेडकरजी की 125वीं जयंती गरिमा व उल्लास के साथ मनाने का सुझाव दिया गया जिसे सर्वानुमति से तत्काल मान्य किया गया।



भारत संचार निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार म.प्र. परिमंडल भोपाल

क्रमांक : एस.आर.-67 /यूनियन/रिकग्नाइज्ड/मेन/बीएसएनएल/2013-14-68 दिनांक 29/10/15

प्रति

श्री प्रकाश शर्मा, परिमंडल सचिव बीएसएनएलईयू इन्डौरा

विषय : बीएसएनएलईयू म.प्र. की ओर से उठाये गए मुद्दों पर लिए गए निर्णय।

संदर्भ: परिमंडल सचिव, बीएसएनएलईयू का पत्र।

उपरोक्त विषय एवं संदर्भानुसार बीएसएनएलईयू यूनियन के द्वारा समस्याओं से अवगत कराया गया था। उन समस्याओं का निराकरण करते हुए विभिन्न विभागों की अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित निराकरण बिन्दु आपकी ओर प्रेषित हैः—

बिन्दु क्रमांक – 1 केबल रखरखाव, टॉवर रखरखाव आदि से संबंधित बिलों के भुगतान के संबंध में सूचित किया जाता है कि बीएसएनएल निगम कार्यालय से मरम्मत एवं रखरखाव के बिलों के भुगतान के लिए नकद आहरण की सूचना दिनांक 20/10/2015 को प्राप्त हुई। उसी आधार पर सी एस सी द्वारा SAP में प्रविष्ट बिलों का भुगतान बिलों की प्रविष्टितिथि के अनुसार नकद आहरण की आंबंटित सीमा के अन्दर किया गया। अभी हाल ही में कार्यालयी व्यय (working expense) के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है।

बिन्दु क्रमांक – 2 बैंक लोन एवं एल आई सी मद पर वेतन कटौती की गयी राशि के ट्रान्सफर में विलंब के संबंध में सूचित किया जाता है कि बैंक लान की किश्त के ट्रॉन्सफर में सी एस सी की ओर से विलंब नहीं हुआ है। यद्यपि निगमित कार्यालय नई दिल्ली द्वारा अक्टोबर 15 में नियत तिथि पर नकद आहरण ट्रॉन्सफर पर नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप विलंब हुआ। इस मामले पर बी एस एल मुख्यालय से चर्चा की जाएगी।

बिन्दु क्रमांक – 3 पन्ना एसएसए में लेखाधिकारी/कनिष्ठ लेखाधिकारी की पोस्टिंग के संबंध में सूचित किया जाता है कि सीधी भर्ती के अंतर्गत एक कनिष्ठ लेखाधिकारी को पन्ना एसएसए में पदस्थि किया गया है (आदेश की प्रति संलग्न) सतना एसएसए से एक और कनिष्ठलेखाधिकारी का ट्रॉन्सफर किया गया है।

बिन्दु क्रमांक – 4 सेवा पुस्तिका में प्रविष्टिका कार्य पूरा करने संबंधी मामले में सूचित किया जाता है कि सेवा पुस्तिका का रखरखाव सभी एसएसए में किया जाता है। यद्यपि, बिजनेस एरिया के आई एफ ए की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश जारी किये जायेगे।

बिन्दु क्रमांक – 5 म.प्र. दूरसंचार परिमंडल में आवासीय क्वार्टर्स व विभागीय टेलीफोन केन्द्र के सिविल मैटेनेंस जैसे पुताई, सीढ़ी रिपेरिंग पानी की टंकी, फूटे टूटे दरवाजे इत्यादि के लिये विगत पांच वर्षों से बी एस एल एवं वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से पर्याप्त मात्रा में बजट आंबंटित नहीं हो पा रहा है। कुछ अत्यावश्यक सिविल रिपेरिंग कार्य एस एस ए प्रमुख की मांग के अनुसार एवं प्रक्कलन स्वीकृति के उपरांत किये जा रहे हैं। अतः समस्त आवासीय क्वार्टर्स का सिविल मैटेनेंस कार्य पर्याप्त मात्रा में बजट आंबंटन होने पर कराया जायेगा।

बिन्दु क्रमांक – 6 केबिल, झापवायर, टेलीफोन, डिसलेम, जम्पर

वायर, इन्सेसर टूल, सुमाकार्ड, बैटरी, फेसटेस्टर, स्वीच बोर्ड आदि सामान की उपलब्धता की समीक्षा की जा रही है एवं सभी एस एस ए को आवश्यकता अनुसार सामान की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

बिन्दु क्रमांक – 7 बिलों के भुगतान की सूचना संबंधित एस एस ए को उपलब्ध कराये जाने संबंधी मामले में सूचित किया जाता है कि बिलों के भुगतान की सूचना पहले से ही mpintranet पर finance-CSC सेक्षन पर अपलोड की जाती है।

बिन्दु क्रमांक – 8 बंद बीटीएस को रवेन्यु के आधार पर समीक्षा की जा रही है एवं आवश्यकतानुसार पुनः चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है।

बिन्दु क्रमांक – 9 समय समय पर परिमंडल कार्यालय में M/s HCL एवं ERP Core Team तथा ITPC Team द्वारा सभी BA के LI को TTT (Train The Trainees) ट्रेनिंग सभी Module की दी जा चुकी है। अतः संबंधित BI को LI के द्वारा सभी एसएसए में End-User ट्रेनिंग का आयोजन कर सकते हैं।

बिन्दु क्रमांक – 10 जीपीएफ/फेस्टिवल/मेडिकल/टी ए बिलों के समय पर भुगतान संबंधी मामले में सूचित किया जाता है कि बीएसएनएल मुख्यालय से नकद आहरण प्राप्त होने के आधार पर सभी दावों का समय पर भुगतान हो इसके हर संभव प्रयास किये जाते हैं।

बिन्दु क्रमांक – 11 जीपीएफ विसंगतियों को दूर करने संबंधी मामले में सूचित किया जाता है कि को टीम की सहायता से अधिकांश जीपीएफ विसंगतियों को दूर कर दिया गया है, मंडला के श्री सुखदेव रजक के प्रकरण में अगले माह समाधान कर दिया जायेगा।

बिन्दु क्रमांक – 12 एसएसए को निर्देशित किया जा रहा है कि सीएससी में उपलब्ध फर्नीचर की समीक्षा करें एवं मानक मापदंडों के अनुसार व्यवस्था करें। सी एस सी स्टाफ के प्रशिक्षण के लिये भी कार्यवाही की जा रही है जिससे कि प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्धता बनायी जा सके।

बिन्दु क्रमांक – 13 ESS सभी कम्प्यूटर पर ठीक ढंग से कार्य करता है। इसके लिए Internet Explorer का उपयोग करना आवश्यक है। ये Internet Explorer Version 10 या अधिक है तो Compatibility view setting में add करके ESS खोलें।

बिन्दु क्रमांक – 14 स्टाफ की कमी नरसिंहपुर एवं अन्य एस एस ए में स्टाफ पोस्टिंग हेतु willingness मंगवाया गया है तदनुसार स्टाफ पोस्टिंग की जायेगी।

बिन्दु क्रमांक – 15 Circle office के IT Section द्वारा CSC को Corporate IT Head में फंड ESS allotment के लिए पत्र लिखा जा चुका है तथा CSC द्वारा विभिन्न जोन को फंड बांटा जा चुका है।

सहायक महाप्रबंधक (संगठन एवं प्रबंधन)
मध्य प्रदेश परिमंडल भोपाल-15



भारत संचार निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)

कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार म.प्र. परिमंडल भोपाल

क्रमांक: एस.आर-4 1/यूनियन/रिक्नाइज्ड/मेन/बीएसएनएलईयू/जन.पत्रा./2013-14/1 दिनांक 29.1.2016

बीएसएनएलईयू के साथ वरि.महाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.) की बैठक के कार्यवृत्त

वरिष्ठ महाप्रबंधक (मा.स/प्रशा.) परिमंडल कार्यालय के कक्ष में दिनांक 25/1/2016 को बीएसएनएलईयू यूनियन के पदाधिकारियों के साथ उनकी समस्याओं के संबंध में समाधान एवं निराकरण हेतु बैठक की गई। जिसमें प्रशासन की तरफ से निम्नलिखित अधिकारी एवं स्टाफ साईड से सदस्य उपस्थित रहे-

स्टाफ की ओर से (1) श्री बी.एस.रघुवंशी, अध्यक्ष, (2) श्री प्रकाश शर्मा, परि.सचिव, (3) श्री एच एस ठाकुर, परि.उपाध्यक्ष, (4) श्री ए के जैन, परि.उपाध्यक्ष, (5) श्री पी.के.तंवर, परि.उपाध्यक्ष, (6) श्री लखन पटेल, सहा.परि.सचिव

प्रबंधन की ओर से (1) श्री एम.एफ.अन्सारी, वरिष्ठ महाप्रबंधक (मा.स/प्रशा.) (2) श्री पी.के.श्रीवास्तव, संयुक्त महा.प्रबंधक (प्रशा./मा.स.)

(3) श्री वाई.के.पोरस, संयुक्त महा.प्रबंधक (सं./प्र.) (4) श्री के.के.स्वामी, उप मण्डल अभियंगता (अ.स.)

माननीय सदस्यगणों का हार्दिक स्वागत करते हुए श्री एम.एफ.अन्सारी, वरिष्ठ महाप्रबंधक (मा.स/प्रशा.) ने श्री प्रकाश शर्मा, परि.सचिव, को मुद्दों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। बैठक में मुद्दों पर सिलसिलेवार एक-एक करके विचार विमर्श किया गया, एवं उन पर उचित निर्णय लिये गये, जो कि निम्नानुसार है:

(1) श्री प्रकाश शर्मा, परि.सचिव, द्वारा मुद्दा उठाया गया कि जिला सचिव को अधिकाधिक कार्यक्रमों में औपचारिक निमंत्रण नहीं दिया जाता है। प्रबंधन ने आगे से इस बिन्दु पर ध्यान रखने की बात कही।

(2) पन्ना एसएसए में सभी लेखा संबंधित कार्य पन्ना एसएसए के द्वारा ही किया जाये :— इस संबंध में वरिष्ठ महाप्रबंधक (मा.स/प्रशा.) ने बताया कि पन्ना एवं सभी दूरसंचार जिला अभियंता स्तर के एसएसए को सीधे संबंधित जोनल महाप्रबंधक को रिपोर्ट करने हेतु आदेश दिया जा चुका है इसके उपरान्त उपरोक्त लेखा संबंधित समस्या स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

(3) श्री सुखदेव रजक का जी पी एफ प्रकरण :— इस मुद्दे पर श्री लखन पटेल ने जानकारी दी कि जीपीएफ एकाउंट अब

इआरपी में दिखने लगा है, किन्तु कुछ सुधार की आवश्यकता है। वरिष्ठमहाप्रबंधक (मा.स/प्रशा.) ने बताया कि इस मुद्दे पर महाप्रबंधक (वित्त) उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

(4) दमोह एसएसए को हॉस्पिटल की सूची में सम्मिलित करना :— श्री प्रकाश शर्मा, ने यह मुद्दा उठाया कि दमोह एसएसए में कोई भी हॉस्पिटल बीएसएनएल के द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रबंधन की तरफ से यह बताया गया कि प्रकरण में दमोह एसएसए को प्रस्ताव मंगवाने हेतु कई पत्र लिखे जा चुके हैं एवं दमोह एवं एसएसए द्वारा एक हॉस्पिटल को सूची में सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर कार्यवाही कर रहे हैं। प्रस्ताव परिमंडल कार्यालय में आगे पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

(5) मोटर ड्राइवर ग्रेड में एनईपीपी डीपीसी का मुद्दा :— इस संबंध में वरिष्ठ महाप्रबंधक (मा.स/प्रशा.), ने जानकारी दी कि 12 मोटर ड्राइवर की डीपीसी समाप्त हो गई है। एवं आदेश भी कर दिये गये हैं। बचे हुये प्रकरण जिसमें कुछ दस्तावेज अपूर्ण थे उनकी भी सूची जारी की जा रही है। वरि.महाप्रबंधक (मा.स/प्रशा.) ने यूनियन के पदाधिकारियों से आहवान किया कि उचित सहयोग के द्वारा अपूर्ण दस्तावेज की उपलब्धता सुनिश्चित करने में प्रबंधन की सहायता करें।

(6) सोसायटी लोन के मासिक किश्त के भुगतान में विलम्ब :— इस संबंध में श्री प्रकाश शर्मा ने ध्यानाकर्षित किया कि सोसायटी/बैंक में भुगतान में देरी की वजह से ब्याज का अतिरिक्त बोझ कर्मचारी पर आ रहा है। इस संबंध में वरि.महाप्रबंधक (मा.स/प्रशा.) ने कहा कि प्रकरण पर महाप्रबंधक (वित्त) को उचित कार्यवाही के लिये लिखा जायेगा।

(7) टेम्प्ररी स्टेट्स मजदूर के प्रेसिडेंसियल ऑर्डर का प्रकरण :— इस बिन्दु प्रबंधन ने बताया कि प्रकरण पर उचित कार्यवाही करने के लिये बीएसएनएल कॉरपोरेट ऑफिस से पत्राचार चल रहा है और शीघ्र ही प्रकरण को समाप्त कर दिया जायेगा। (खंडवा प्रकरण)

(8) स्प्लाईसिंग मशीन एवं ओटीडीआर मशीन की अनुपलब्धता :— यह मुद्दा उठाते हुये श्री प्रकाश शर्मा, ने बताया कि पीथमपुर (धार) जो कि उच्च राजस्व का क्षेत्र है, यहां भी उपरोक्त मशीन की अनुपलब्धता की वजह से फाल्ट

ठीक करने में देरी होती है। प्रबंधन ने इस संबंध में संबंधित यूनिट को उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की बात कही।

(9) **मेडिकल बिलों के सम्बन्ध में** :— इस मुद्दे पर श्री प्रकाश शर्मा, ने बताया कि अभी कुछ प्रकरण जैसे — सेवा निवृत्त या निकट भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों का निपटान नहीं हो रहा है, फलस्वरूप ली गई अग्रिम राशि को उनके सेवा निवृत्त लाभ में समायोजित किया जा रहा है। इस संबंध में प्रबंधन ने यूनियन के पदाधिकारियों से विशिष्ट प्रकरण से अवगत करने को कहा गया। इस संबंध में निम्नलिखित प्रकरण अवगत कराये गये:

1. श्री एस डी शर्मा, जबलपुर। 2. श्री मुस्ताक अहमद, इन्दौर। 3. श्री मो. शरिफ खान, इन्दौर। 4. श्री विनोद कुमार, जबलपुर। 5. श्रीमति शान्ता बाई दुर्गेश राठौर, इन्दौर। 6. श्री प्रमोद त्रिवेदी, रतलाम। 7. श्री लक्ष्मी सिंह कुशवाह, उज्जैन। 8.

विगत दिनों नवंबर 2015 से जनवरी 2016 तक जीपीएफ भुगतान हेतु हमने काफी प्रयास किए एवं वेबसाईट के माध्यम से वस्तुस्थिति से सभी को अवगत कराया, अन्य यूनियन फंड नहीं आया, फंड नहीं आया का विलाप करती रही। जी पी एफ भुगतान... चिंताजनक स्थिति वेबसाईट पर प्रसारित

जी पी एफ भुगतान में विलम्ब निः संदेह हमारे साथियों के लिए बेद्द विवरणी का सबब है। किसी के यहाँ शादी, किसी के इलाज के लिए रुपयों की जरूरत तो किसी को भवन निर्माण हेतु एक बड़ी राशि की आवश्यकता। सब कुछ जीपीएफ पर निर्भर है। आपकी इस चिंता से हम वाकिफ हैं और चिंतित भी हैं।

हमेशा की तरह फंड रिलीज में देरी को देखते हुए हमारे महासचिव ने कॉर्पोरेट ऑफिस में चर्चा की। फंड रिलीज करने हेतु कॉर्पोरेट ऑफिस के एक जिम्मेदार महाप्रबंधक ने कॉ पी अभिमन्यु को हर हाल में 11.1.2016 तक जी पी एफ भुगतान का विश्वास दिलाया। तदनुसार हमने भी यह जानकारी हमारे साथियों के मध्य प्रसारित की थी। शायद सदस्यों को स्थिति से अवगत करवाना कोई गुनाह नहीं है, वरन् यह एक जिम्मेदारी है। किन्तु परिस्थितियों वश फंड जारी नहीं हुआ। ऐसे में फंड नहीं आया, फंड नहीं आया का विलाप करने की बजाय अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन करते हुए हमारे महासचिव ने 13.1.2016 को हमारे माननीय सी एम डी श्री अनुपम श्रीवास्तवजी को कर्मचारियों की परेशानी से अवगत करवाया। सी एम डी महोदय ने स्पष्ट किया कि पूर्व में जी पी एफ हेतु बीएसएनएल द्वारा खर्च की गई राशि का भुगतान अभी तक डी ओ टी द्वारा न किए जाने से हमारी वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है। यह राशि करोड़ों में है। इस स्थिति में जी पी एफ भुगतान केवल बैंक से 9.5% की ब्याज

बधाई.. हमारे 25 और साथी टीटीए बने.....!

टीटीए का रिजल्ट रिव्यू हुआ। अब हमारे 25 और साथी टीटीए बनेंगे। बधाई !

इस संबंध में बीएसएनएलईयू के परिमंडल और सीएचक्यू द्वारा किए गए परिणाम मूलक प्रयासों से सभी वाकिफ हैं और हमारे ठोस प्रयास अंततोगत्वा सफल परिणामों में परिणित हुए इस बात की आपके साथ हमें भी बेहद खुशी है।

श्री आरके शर्मा, उज्जैन। 9. श्री पी सी चौरसिया, उज्जैन।

इन प्रकरणों पर प्रबंधन प्राथमिकता पर निपटान सुनिश्चित करेगा।

(10) **यूनियन की चन्दा कटौत्री सूची के संबंध में** :— श्री एच एस ठाकुर, ने इस संबंध में बताया कि जनवरी—2015 से जनवरी—2016 की यूनियन चन्दा कटौत्री की सूची एसएसए वाईज उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस संबंध में वरिष्ठ महाप्रबंधक (मा.स/प्रशा.) ने संबंधित अनुभाग को उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करने को कहा।

(11) **श्रीमति शिखा महाडिक**, वरि.दूर.कार्या.सहा. का जबलपुर टीटीसी /एसएसए में 2 माह का वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। यह प्रकरण शीघ्र सुलझाया जाएगा।

बैठक के समापन पर बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।

दर से लोन लेकर ही किया जा सकता है। कॉ अभिमन्यु ने उन्हे स्पष्ट कहा कि चाहे जो करना पड़े, जी पी एफ भुगतान शीघ्र होना चाहिए। बीएसएनएल एम्प्लाईज यूनियन ऐसी गंभीर स्थिति में एक मूक यूनियन बनकर नहीं रह सकती और फंड नहीं आने की स्थिति का आनंद की अनुभूति के साथ उपहास करने की बजाय जी पी एफ का शीघ्र भुगतान कैसे हो इस हेतु चिंतित हैं एवं सतत प्रयासरत भी। अपने प्रयासों के तहत हमारे महासचिव ने टेलीकॉम कमिशन में मेंबर (फायनेंस)को भी डी ओ टी को जी पी एफ की बीएसएनएल को देय राशि का भुगतान करने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा है। बीएसएनएलईयू की हर समस्या के निदान और विभिन्न सुविधाओं को प्रदान करवाने में सदैव अग्रणी भूमिका रही है। इस हेतु हम सतत संघर्ष कर भी रहे हैं क्योंकि बीएसएनएलईयू उस नीरो का अनुसरण नहीं करती जो उस वक्त भी बंसी बजा रहा था जब रोम जल रहा था।

हमें कर्मचारियों की पीड़ा का पूर्ण अहसास है और उम्मीद है हमारी कौशिशों से शीघ्र ही भुगतान की राह आसान होगी। लेकिन हाँ, जीपीएफ का भुगतान पूर्ववत सुगमता से होता रहे इस हेतु भी अब कोई ठोस निर्णय होना चाहिए ऐसा हम महसूस करते हैं और बीएसएनएलईयू इस दिशा में भी शीघ्र पहल करेगी।

सभी सफल मित्रों को बधाई....! और

हमारे महासचिव कॉ पी अभिमन्युजी का परिमंडल की ओर से आभार....

जेटीओ के रिजल्ट रिव्यू के लिए भी प्रयास जारी है.... और शीघ्र कामयाबी की उम्मीद भी है....

देखते रहिए www.bsnleump.com

परिमंडल सचिव का० प्रकाश शर्मा द्वारा माननीय मुख्य महाप्रबंधक को विभिन्न समस्याओं हेतु लिखे गए पत्र

Sub: Regarding reimbursement of medical expenses in r/o Shri O P Sharma of Sagar.

Res Sir,

Shri O P Sharma, Secretary Local Council, Sagar, underwent bypass surgery at Indore in a recognized Hospital. Due to negligence of Hospital his condition became critical & he was forced to rush immediately to Coimbatore for further treatment. Any delay in moving to Coimbatore Hospital would have had resulted in amputation of his leg. He has incurred a big amount towards medical expenses but reimbursement is done for a meagre amount & the case is closed citing various reasons without considering the human aspects of the case. Shri O P Sharma is our firebrand leader and he used to take up staff related issues with Sagar administration. Owing to this The SSA Head has adopted vindictive attitude & overlooking the human ground he did his best to get the bills rejected, it is felt. The case has been discussed at length in Circle Council meeting & it was principally agreed to reconsider the same.

Now , it is requested to settle his case in Medical Adalat on 7.11.2015 & provide him financial relief. He has already submitted all papers and are available in circle office. One copy of the letter is attached h/w which is self explanatory.

Hope, the case will be settled with positive approach.

का० पी.अभिमन्यु, महासचिव को पत्र

Sub : Regarding discrepancy in Result of TTA LDCE.

Res Comrade,

LDCE for the promotion to the grade of TTA under 50% quota for the recruitment year 2014 was held on 7.6.2015 & provisional result is declared on 31.8.2015. More than 300 candidates appeared in the exam but only 9 have been declared successful. The reason behind poor result is inclusion of out of course questions of 6 marks in paper 1 & of 1 mark in paper 2. The result is declared on the basis of 93 marks. Our demand of awarding 7 marks to all candidates for out of course questions is refuted by management under the plea of Hon'ble supreme court decision of not allowing any grace marks.

Our demand is not grace marks...it is just the compensation for out of course questions. Further, the result should be based on 100 marks & not 93. If 7 marks are given to all candidates , many of them will be declared successful.

Recently the Result declared by Andhra Circle carries 2 marks to all candidates for inclusion of out of

course questions. On this basis MP Circle candidates should also get 7 Marks to all for out of course questions and Result may be declared on the basis of 100 marks.

It is requested to kindly do the needful in this regard.

Sub : Regarding allotment of T CODE/role authorization for pa30.

Res Sir,

The staff of Jabalpur Civil Division no.1 are facing hardships in getting their claims settled...viz GPF, MEDICAL etc in absence of the T CODE/role authorization for pa30 for processing claims in ERP. The request letter for allotment of T CODE/role authorization for pa30 has already been sent by Chief Engineer (Civil), BSNL Civil Zone, MP East, Jabalpur on dated 25/08/2015. It is unfortunate that the issue of the required code is pending till date despite submission of request in Aug 2015.

Hope, you will expedite the same immediately for smooth release of the claims of staff.

This may kindly be treated as MOST URGENT as it is already delayed.

Sub : Regarding allotment of T CODE/role authorization for pa30.

Res Sir,

The staff of Jabalpur Civil Division no.1 are facing hardships in getting their claims settled...viz GPF, MEDICAL etc in absence of the T CODE/role authorization for pa30 for processing claims in ERP. The request letter for allotment of T CODE/role authorization for pa30 has already been sent by Chief Engineer (Civil), BSNL Civil Zone, MP East, Jabalpur on dated 25/08/2015. It is unfortunate that the issue of the required code is pending till date despite submission of request in Aug 2015.

Hope, you will expedite the same immediately for smooth release of the claims of staff.

This may kindly be treated as MOST URGENT as it is already delayed.

Sub : Regarding posting of AO at Panna SSA and JAO at Chhatarpur SSA

Res Sir,

As you are aware in Panna SSA no Accounts Officer is posted till date. AO Panna was relieved for Satna on 15.06.2013 & thereafter the post is lying vacant & it is very unfortunate to inform you that Panna is only SSA in MP where AO's room is locked since last two years.

Sir , in absence of AO the employees & officers of Panna are facing lot of hardships in settlement of their

personal claims. Entry in Service Books & verification of the same is pending. Simultaneously, the DSA / Franchises have also resented the absence of AO. Disappointment amongst staff & DSA etc is growing day by day & may result in loss of revenue.

Sir, the issue has been discussed with you on earlier occasions. GMF has also assured in Sept 2015 about posting of AO at Panna latest by first week of Oct 2015. But the posting orders are still awaited.

Similarly, one JAO is to be posted at Chhatarpur for smooth functioning of accounts unit. The Chhatarpur staff is also facing same problems as in Panna SSA.

Sir, hope you will instruct soon for the posting of AO & JAO to arrest the unrest.

Sub : Regarding partisan attitude of Two SSA Heads.

Res Sir,

I would like to invite your kind attention towards partisan attitude of SSA Heads of Jabalpur & Khandwa with a request to advise them to avoid their dilly dally & partisan attitude towards the legitimate demands.

Sir, in BSNL right from Res CMD to an ordinary but sensible Employee, all are exerting hard for the betterment of BSNL. We appreciate that Circle & Corporate Heads are pouring in their best to create an atmosphere to enrich Industrial Harmony. We observe that The Top Brass of the company feel that this harmony is must at this juncture. But at the same time I am constrained to inform you that some SSA Heads feel otherwise & are leaving no stone unturned to put the SSA, they are heading, in confrontation mode.

Sir, Mr. B K Jog, Snr GMT Jabalpur is bent upon to instigate our young leaders & disrupt peace. Our Jabalpur District Union was forced by Jabalpur management to resort to an agitation which continued for two months. The Snr GMT shown a lackadaisical attitude & never bothered to resolve the legitimate issues in a true spirit despite the fact that most of the demands in charter of demands were for the betterment of the company. Still, on our persuasion, our District Union deferred the agitation hoping that good sense will prevail upon the authorities but in vain.

Sir, now Snr GMTD Jabalpur has resorted to " Divide & Rule Strategy " & favoring a particular union by transferring their members at his (GM's) & their (union's) whims & fancies while our justified demands remain unheard & our members are deprived of the justice. Our JABALPUR DS has requested repeatedly to GMTD to issue transfer order in r/o one of our member Mr. Anil Kashyap who was denied of the benefit of relaxation in transfer on spouse ground & was wrongly transferred in rural area. His request remained unconsidered for a long time & now he is on the verge of completion of the tenure period. Sir if a wrongly transferred official is

transferred 3-4 months prior to end of tenure, heaven is not going to fall in Jabalpur. The most irritating part of this issue is other two employees have been considered for the relaxation on the same ground by the same GM. Our Leaders tried to resolve the issue in a peaceful way but Mr. Jog is inciting our Young Brigade & forcing them to resort to harsher trade union action & if this happens, the act of neglect & negative attitude of Mr. B K Jog will only be fully responsible for the disruption of the cordiality.

Sir , I understand that SSA matter should not be brought to Circle Head but confrontation scenario is gaining momentum day by day due to adamancy & Circle intervention is must to resolve the issue. As such I do request you to advise Mr. Jog to pay heed to the genuine demand of our Jabalpur District Union & utilize the energy of our young leaders for the financial growth of the company.

Similarly, it is felt that Khandwa Management is also no different from Jabalpur. The Existing TDM & his predecessor, both have played their role in creating a rift between the employees. They issued transfer orders on pick - n - choose basis. The orders issued were held in abeyance thrice & relieving orders were also issued thrice. This proves that management itself is doubtful of its own action & it is a sheer mockery of the transfer process. Further, those who are on the top in longest list are working at Khandwa as they enjoy the support of some powerful hand in management. Our Khandwa Union has requested to cancel the order of 4 Snr TOAs & also proposed that if needed the same may be issued in next session. Union argued that relieving in the mid session will be a physical, mental & social torture for the employees. But Khandwa management is adamant & submitting lame excuses. Both the TDMs of Khandwa blatantly informed that all the action has been taken at the behest of CGM & hence the orders can't be reversed without CGMs intervention. We don't think that there is any role of Res CGM on such petty matter & understand the hollowness of the excuse rendered by the TDMs.

In this rigid scenario created by both TDMs in Khandwa We request to advise suitably to Khandwa management for immediate cancellation of the orders till the next session. If cancellation of transfer order is not possible, transfer those who are staying since a long time in Khandwa. But the first option of cancellation of orders will be more human, we feel.

We expect & hope justice from You in both cases.

Sub: Regarding change of place of posting.

Res Sir,

I am thankful to you for taking keen interest in issuing the appointment orders of 128 candidates on compassionate ground.

Out of these, some of them , specially lady

candidates, have requested change of the SSA on family ground as their family is shifted elsewhere from the SSA wherefrom they had applied for the job. As such this will burden them with the additional expenditure of maintaining double establishments in addition to other hardships they would face.

We do request you to consider the cases on the merit & genuineness of the same.

Sub : Regarding recognition of Hospital at Damoh

Res Sir,

Our District Secretary has intimated that in Damoh no Hospital is recognised by BSNL for treatment of the employees working there. It is astonishing that No one has taken initiative in this regard despite several requests by our DS.

Sir, You have always shown your concern on welfare matters of the staff & as such I do request you to issue suitable instructions to your subordinates to pursue the recognition issue.

Sir, A very quick action on the matter will be a big solace to the employees of Damoh facing various ailments.

Sub : Regarding confirmation of TTAs & refund of security amount.

Res Sir,

It is learnt that in many SSAs confirmation orders are not issued to the TTAs despite a lapse of 4-5 years. This is perhaps due to a lackadaisical attitude of the concerned unit Heads. All the TTAs waiting for confirmation are feeling dejected.

Owing to Non-issue of confirmation orders, the TTAs have not been refunded the security deposit of Rs 5000/- too..

I do request you to kindly instruct all the SSA Heads to take immediate action for release of confirmation orders along with the refund of security amount to the TTAs.

Sir, A very quick action on the matter will be a big solace to the TTAs.

Sub: Inclusion of staff working in Western Telecom Project in gradation list of concerned SSA.

Sir,

I wish to bring your kind notice that the gradation list at SSA level and Circle level has not been incorporated the non executive staff in various cadres i.e Sr. TOA, Telecom Mechanic, TTA, RM & Motor Drivers who were transferred from parent SSA to local SSA as per guidelines and orders of MP Circle and working on deputation to their existing unit, in the gradation list of

different SSA i.e. GMTD Bhopal/GMTD Gwalior/GMTD Jabalpur/GMTD Indore.

As a result of this the promotion in the Grade I, II, III and special grade in the cadre of Motor Driver is pending in CGM office since long also the promotion in other non-executive cadres like Sr. TOA, TTA, TM, RM under the non executive promotion policy will affect the timely issue of promotion orders. I solicit to your personal attention to ensure to bring up to date gradation list in all the non executive cadres in Circle and all SSA concerned specially GMTD Bhopal/Gwalior/ Jabalpur/ Indore.

Sub : Regarding AGITATIONAL ACTION IN M P CIRCLE AGAINST ACT OF PROVOCATION BY JABALPUR MANAGEMENT

Res Sir,

I would like to invite your kind attention towards act of provocation by Jabalpur Management .

Sir, in our earlier letter we have brought to your notice about the lack of managerial skills in Jabalpur Management and as to how they are making mountain of the mole hill and creating a scenario of confrontation in Jabalpur. This is perhaps a big reason behind hampering of revenue growth in the SSA. Month before our District Union submitted an agenda with maximum points comprising the issues related with the growth of BSNL. But the lethargic management did not pay any attention to resolve the issues raised in the agenda. Our union has already made it clear that if the issues are not resolved they will left with no option but to resort to trade union action and according to the notice of the union , an indefinite dharna will be staged with effect from 19.11.2015. But with deep concern I am constrained to inform you that the management gave a routine reply and to our dismay and much to the chagrin of our local union they issued a threatening letter with warning of stern action if the union indulge in any agitational program. The management should have called our union, discuss the issues with them and then should have issued any letter. But they violated all norms and with the aim of provocation the threat letter is issued.

Sir, in our secretariat meeting held on 16.11.2015 the issue was viewed seriously. This is the blatant attack on trade union rights of the recognized union and an act of curbing the legitimate action. To protest this, our Circle Union has decided to launch an agitational program all over SSA against the illegitimate cowardly act of the Jabalpur Management. The Circle will demonstrate during lunch hours all over MP once in a week till the things are mend in Jabalpur. The dates will be intimated later on. In the meanwhile we urge to advise the Jabalpur authorities to create a cordial atmosphere and utilize the man power for the growth of

BSNL instead of entering into frequent childish quarrels with the union. Hope good sense will prevail upon them.

Sub: Regarding NGN problems at Indore.

Res Sir,

As you are aware , NGN technology was inaugurated on 14.03.2015 by our Hon'ble Minister to provide advanced value added services like video calls, video conferencing etc to our land line customers. This came as a boon for the customers & for us too. It was expected that introduction of the state-of-art technology facilities will curb the exodus of customers & will fetch more landline customers. But so far as Indore is concerned the boon has converted into a bane. Conversion in NGN is started in a phased manner but no efforts have been made to apprise the customers of the facilities of NGN despite request by Union. Further, the customers in centrax groups who have been switched over to NGN are facing many problems like abbreviated dialing, creation of lock code etc. The authorities are unable to explain & satisfy the customers. The PRI customers are at mercy of the BSNL Authorities who are showing lethargy in mending the problem.

Sir, recently 1000 connections were migrated to NGN. I am constrained to inform that in the process some 250 no reported faulty due to wrong jumpering which was done on the basis of the list provided to the staff which itself was erroneous. This shows utter negligence of the in charge.

If such attitude continues, I am afraid, we will lose a good no of customers. Looking into the seriousness of the issue, You are requested to intervene to avoid the big loss to BSNL both due to reduction of Landline customers & reduction in revenue. The letter of our DS addressed to GMTD Indore is also attached h/w which explains the grim situation in detail.

Sub: Immediate Action in Rewa Issue.

Res Sir,

You have already been apprised of the Rewa Issue by the Delegation of Forum of BSNL Unions & Associations on 17.12.2015. In this regard a meeting of Forum was held today wherein it was unanimously decided to demand the following.

1. It has been re-affirmed in Forum meeting that *prima facie* evidences are indicative of alleged indulgence of TDM Rewa in the heinous, abhorrent, nasty & inhuman act. TDM's written acceptance given to police (as circulated on WHATSAPP ...copy enclosed subject to authenticity) is self explanatory. As such it is demanded to transfer the alleged officer immediately from Rewa with recommendation of his repatriation to DOT so that the image of Company is not maligned further.

2. The Forum was also apprised of resentment

amongst Local Forum of Rewa on TDM Rewa's intrusion in office on 18.12.2015 despite the fact that his charge was handed over to TDM Satna. He should be strictly warned to remain away from the office.

3. It is also demanded to include 3 members from Forum in the departmental enquiry committee to probe the facts. Management may go ahead with vigilance enquiry as per procedures.

4. An immediate enquiry & decision of punishment based on the outcome of the investigation reports be taken.

5. It has been brought to notice of Forum that the victim is being pressurised by some responsible officers to compromise. Such officers be advised to refrain away from the threat actions.

6. The Forum will raise slogans to condemn the act during the demonstrations on 22.12.2015.

7. Forum is confident that justice will not be denied & the stringent action against the culprit will be taken soon to instil confidence in a large section of employees who are reeling under frightened feel.

Sub : Regarding manhandling, abusing & threats by DSA with TTAs and other staff at Shyopur, Morena SSA.

Res Sir,

I have been informed about the Shyopur incidence. On the basis of information gathered I am submitting the facts to you. The incidence was immediately reported to you through whatsapp.

Sir, A team comprising Shri Ravindra Singh, TTA, Shri Siyaram Meena, TTA, Shri R C Sharma , SDO & others are actively involved in Mela activities in Shyopur and fetching handsome business. One DSA Mr Ghanshyam Goyal was feeling uncomfortable due to our active team as his business was being hampered. He is in habit of entering into altercations for one reason or other. Yesterday morning he did unpleasant behaviour, abused staff & threatened them of life. He was furious as staff was doing CAF entries of mela forms & he was insisting to give priority to his forms. It has been reported that He tried to ransack our canopy too. When our BSNLEU Leader Mr R K Shrivastav tried to pacify him. Mr Goyal provoked him & threatened him of dire consequences. Under provocation & in retaliation Mr Shrivastav might have had exchanged some unpleasant words, as complained. Mr Goyal has perhaps sent you the distorted recording.

I am also informed that Shri Ravendra Singh TTA is a hard working employee & he was manhandled by the said DSA Shri Ghanshyam Goyal. Had our SDO not intervened, DSA would have had beaten him. There are evidence of his interference in working, abusing & threats of dire consequences. On this basis the DSA deserve stern action against him & He should be

debarred from working as DSA too immediately.

DSA has complained to police & it is learnt. that a complaint has been lodged in police station by our SDO Shri Sharma too.

I request you to intervene suitably to create an amicable and business conducive atmosphere.

Any action on our staff in a haste may dampen their spirit & this will kill the enthusiasm created amongst us & will be a cause of tussle.

Hope you will do the needful.

Sir, A very quick action on the matter will be a big solace to the TTAs.

Sub: Regarding Review of result of TTA LDCE under 50% quota held on 7.6.2015

Res Sir,

I would like to invite your kind attention towards letter no 37-1/2015- Rectt dated 24.2.2016 issued by Recruitment Branch of Corporate office on the matter under subject. As you are aware 7 questions were out of syllabus in the said examination and union was demanding to award additional marks for the wrong questions. Our CHQ did lot of efforts for this. Now the clarification on evaluation is received and it is clearly mentioned in the aforementioned letter to award full 7 marks for the out of syllabus questions.

It is learnt that a committee is constituted to review the result and declare the same again in r/o successful candidates who are eagerly waiting for the outcome. But It is matter of great concern that the process is being delayed un-necessarily. If someone in the committee is on leave, as is informed, he should be replaced and expedite the action. Corporate Office Management is also of the view that it is in the interest of the organization to fill maximum number of vacancies in TTA Cadre. As such it is demanded to review and declare the result immediately in the interest of the organization.

Sub: Regarding promotion of Motor Drivers.

Res Sir,

I would like to invite your kind attention towards inordinate delay in promotion of Motor Drivers in various SSAs in the Circle. The issue was discussed earlier in meeting dated 25.1.2016 and on many occasions in past. A letter was also given in this regard. With the efforts of our union the DPC was held and promotion orders were issued in r/o some Motor Drivers. But many cases were not considered for want of various information or documents from the SSAs in the DPC. Motor Drivers from Gwalior and Jabalpur SSAs are most sufferers as reported by our District Secretaries. As such I do request you the following in this regard.

1. Invite all the cases due for promotion from all SSAs.

2. SSA Heads should be suitably instructed to send the cases in complete manner.

3. Hold the DPC immediately and issue the promotion orders.

4. The process should be completed as early as possible in a prescribed time frame.

Hope Circle Management will act immediately to curb growing resentment amongst the aspirants.

Sub : Regarding FACILITY OF OFF NET CALLS ON FREE SIM.

Res Sir,

A letter from Corporate Office is issued to provide Off Net calls facility amounting to Rs 50/- every month on the FREE SIM provided to all nonexecutives wherein free On Net calls amounting to Rs 200/- were being provided till date. According to the Corporate Office Letter the facility to charge with Top Up if the calls amounting to Rs 200/- are consumed is to be provided.

Reports are pouring in from many circles that the facility of Off Net calls and Top Up is started in the Circles. But Non Executives in M P Circle are deprived of the facility. It is requested to advise the Authorities concerned to implement the Corporate Office Orders immediately.

A very quick action is expected as the matter is already delayed.

विगत 11 वर्षों में 5 गुना सैलरी बढ़ी

बीएसएनएल एम्प्लाइज युनियन को मान्यता मिलने के बाद मात्र 11 वर्षों की अवधि में 1.1.2007 से देय शानदार वेतनमान और ऐतिहासिक प्रमोशन पॉलिसी (NEPP) की वजह से कर्मचारियों की सैलरी में 5 गुना बढ़ोत्तरी हुई है और उनके जीवन स्तर में प्रशंसनीय सुधार भी आया है। हाल ही में कोयम्बटूर के एक सीनियर टीओए कॉ. वेंकटरमन ने हमारे महासचिव को पी अभिमन्यु को धन्यवाद देते हुए सूचित किया है किया कि सन् 2004 में वे रु. 15,649/- वेतन प्राप्त कर रहे थे और फरवरी 2016 में उन्होंने रु. 76,341/- वेतन प्राप्त किया है। कमोबेश सभी इसी अनुपात में लाभांवित हुए हैं।

जीवन स्तर में श्रेष्ठता और वेतन में अभूतपूर्व इजाफा...वह भी मात्र 11 वर्षों में...अद्भुत। बीएसएनएल एम्प्लाइज युनियन के प्रयासों से हासिल इस उपलब्धि के लिए हमारे नेतृत्व का नमन।



मेडिकल बिलों के सहज भुगतान हेतु प्रबंधन को प्रेषित सुझाव पत्र

No.BSNLEU / M PCIRCLE/ PROBLEMS/ 9

DATE:3/11/2015

प्रति ,
डॉ. गणेश चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार
बीएसएनएल, मध्य प्रदेश परिमंडल, भोपाल.

विषय :- मेडिकल बिल निपटान हेतु सुझाव

माननीय महोदय,

मध्यप्रदेश परिमंडल में मेडिकल बिलों के पैंडिंग होने की गंभीर समस्या है जिसे परिमंडल प्रबंधन ने संजान में लेते हुए 17 अक्टूबर 2015 को मेडिकल अदालत का प्रावधान रखा था जिसमें आंशिक परिवर्तन करते हुए 17 अक्टूबर 2015 को मेडिकल बिलों की समीक्षा बैठक एवं 7 नवम्बर 2015 को मेडिकल अदालत की सूचना जारी की गई है। विभिन्न अधिकारियों एवं फील्ड स्टाफ से चर्चा से निष्कर्ष यह निकल रहा है कि मेडिकल अदालत के अलावा मेडिकल समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित सुझावों पर अमल करने से मेडिकल बिल भुगतान को गति मिलेगी

- (1) मेडिकल बिलों के सम्बन्ध में यूनियन को चेक लिस्ट प्रदान की जाए।
- (2) मेडिकल बिलों के सम्बन्ध में सभी नियमावली प्रदान की जाए।
- (3) बीमारियों के पैकेज रेट, आपतकालीन इलाज, सर्किल से बाहर इलाज, प्रायवेट हॉस्पिटल से इलाज, बेडचार्जेस, नार्मल इलाज आदि के सम्बन्ध में रूलिंग के साथ फोरम के लीडर्स को दस्तावेज सहित जानकारी दी जाए।
- (4) इस सम्बन्ध में ट्रेनिंग सेंटर में वर्कशॉप/ट्रेनिंग प्रोग्राम विथ प्रोजेक्टर कोर्स बनाया जाए जिस तरह से विजिलेंस कोर्स बनाया गया है। स्टाफ को समय समय पर उसकी बारीकियों को समझाना जरुरी है कि यदि अचानक से हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो किन-किन बातों का ध्यान रखना जरुरी है।
- (5) SSA द्वारा लेखा अधिकारी मेडिकल बिलों को ध्यान से चेक करके भेजा जाना चाहिए यदि SSA द्वारा अधूरा बिल परिमंडल भेजा जाता है तो सम्बंधित पर कार्यवाही होना चाहिए।
- (6) समस्त नियमों को ध्यान में रखते हुए एक सरल प्रक्रिया बिलों के निराकरण की बनाना चाहिए कि किन परिस्थियों में इलाज कराया गया, आपतकालीन इलाज इत्यादि।
- (7) अभी डिपेंडेंसी के मामले में परिमंडल द्वारा आपत्ति लगाई जा रही है कि सर्विस बुक से वेरिफिकेशन होना चाहिए जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेडिकल कार्ड सर्विस बुक से वेरिफाई होकर ही बनता है।
- (8) यूनियन के द्वारा मेडिकल अदालत में जो भी प्रकरण दिए जा रहे हैं उन प्रकरणों को परिमंडल तुरंत वापस बुलाये उन बिलों में जो भी समस्या/आपत्ति है उसे यूनियन को सूचित करें। मेडिकल अदालत में यह जबाब संतोषपूर्ण नहीं होगा कि इस बिल में यह आपत्ति है SSA भेज दिया गया है।
- (9) उपरोक्त सुझावों का इम्प्लीमेंटेशन 7 नवम्बर 2017 की अदालत से पहले किया जाएगा तो मेडिकल अदालत सफल होगी।

आदर सहित,
(प्रकाश शर्मा)

बीएसएनएल और बीएसएनएल कर्मियों के हितसंवर्धन के लिए निरंतर...सतत...अनवरत रूप से प्रयासरत हमारे महासचिव कॉ.पी.अभिमन्यु को उनके नेतृत्व में अर्जित असंख्य उपलब्धियों के लिए म.प्र. परिमंडल की ओर से शुक्रिया...दिल से।



परिमंडल अधिवेशन, सेमीनार एवं नई कार्यकारिणी का चयन.

बी.एस.एन.एल. एम्प्लाईज यूनियन, म.प्र. परिमंडल का अधिवेशन भोपाल में दि. 8.8.2015 एवं 9.8.2015 को संपन्न हुआ। कॉ. बी.एस. रघुवंशी, परिमंडल अध्यक्ष, बी.एस.एन.एल.ई.यू. ने अध्यक्षता की। अधिवेशन में श्री गणेशाचन्द्र पाण्डेय, मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. परिमंडल के मुख्य आतिथ्य में सेमीनार भी आयोजित किया गया, जिसे कॉ. बादल सरोज, प्रदेश सचिव सीटू एवं बीएसएनएलईयू के महासचिव कॉ.पी. अभिमन्यु ने संबोधित किया। इस दौरान कॉ. जगदीश सिंह यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सहयोगी यूनियन एसोसिएशन के प्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। दि. 9.8.2015 को कॉ. पी. अभिमन्यु, महासचिव की उपस्थिति में सर्वानुमति से निम्न कार्यकारिणी का चयन किया गया।

परिमंडल अध्यक्ष	कॉ. बी.एस. रघुवंशी	(नरसिंगपुर)
परिमंडल उपाध्यक्ष	कॉ. एच.एस. ठाकुर	(भोपाल)
	कॉ. एम.एल. चौधरी	(इन्दौर)
	कॉ. ए.के. जैन	(भोपाल सिविल विंग)
	कॉ. पी.के. तंवर	(भोपाल)
	कॉ. ओमप्रकाश सिंह	(भोपाल डब्ल्यूटीपी)
परिमंडल सचिव	कॉ. प्रकाश शर्मा	(इन्दौर)
सहा. परिमंडल सचिव	कॉ. बालेन्द्र कुमार परसाई	(भोपाल)
	कॉ. योगेश शर्मा	(सतना)
	कॉ. लरवन पटेल	(जबलपुर)
	कॉ. सलामत अली	(भोपाल)
	कॉ. राकेश यादव	(ब्वालियर)
परिमंडल कोषाध्यक्ष	कॉ. एस.एन.एस. चौहान	(जबलपुर)
परिमंडल उपकोषाध्यक्ष	कॉ. सुनील करण	(भोपाल)
परिमंडल संगठन सचिव	कॉ. मनोज चौरसिया	(रायसेन)
	कॉ. भागचन्द	(होशंगाबाद)
	कॉ. आर.एस. होश	(इन्दौर)
	कॉ. डी.के. मेश्राम	(बालाघाट)
	कॉ. दीपक शर्मा	(खरगोन)
	कॉ. आर.एस. बेलगोत्रा	(उज्जैन)
	कॉ. श्रीमती मीना चौरङ्गिया	(इन्दौर)
ऑडीटर	कॉ. एस.डी. शर्मा	(जबलपुर)

सी.ई.सी. मेम्बर्स (विशेष आमंत्रित) :-

कॉ. व्ही.एम. पराते (मंदसौर), कॉ. पी.एल. सामरे (खण्डवा), कॉ. बी.एस. दावडे (छिंदवाडा), कॉ. मूलचंद सोनी (सागर), कॉ. आर.एस. कुशवाह (उज्जैन), कॉ. सतीश चौहान (मुरैना) कॉ. एस.सी. श्रीवास्तव (भोपाल), कॉ. जी.जे. शेख (ब्वालियर), कॉ. डी.एस. रघुवंशी (ब्वालियर), कॉ. राशिद अली (भोपाल), कॉ. अतिराम सिंह (ब्वालियर), कॉ. जी.पी. गर्फ (गुना), कॉ. जगदीश सोनी (इन्दौर), कॉ. एम.के. उके (भोपाल).

नोट : सी.ई.सी. मेम्बर्स को वोट डालने के अतिरिक्त कार्यकारिणी को प्राप्त सभी सुविधायें मिलेंगी।

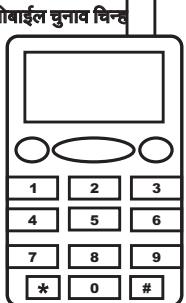
बीएसएनएल कर्मियों की एकता, संघर्ष, विश्वास व विकास की प्रतीक आपकी अपनी



बी.एस.एल. एम्प्लाइज यूनियन

म.प्र. परिमंडल, भोपाल

मोबाइल चुनाव चिन्ह



पर मोहर लगाए यह निवेदन...

हमारी उपलब्धियां

- ★ संयुक्त संघर्ष में सभी की सहभागिता में सफलता
- ★ बी.एस.एन.एल. के हित संवर्धन हेतु सभी संगठनों से सामंजस्य स्थापित कर संघर्ष
- ★ उपकरणों की आपूर्ति हेतु निरंतर प्रयास
- ★ 11 वर्ष के कार्य काल में असंख्य उपलब्धियों की एक लंबी फेहरिस्त/सूची
- ★ बी.एस.एन.एल. में विनिवेश को रोकने में सफल
- ★ बी.एस.एन.एल. के शेयर बेचने की सरकारी योजना विफल की
- ★ बी.एस.एन.एल. का केबल निजी कम्पनियों को देने की योजन असफल की
- ★ पित्रौदा पेनल की सिफारिशों पर रोक में सफलता
- ★ 1 लाख कर्मियों की छंटनी योजना पर रोक
- ★ विपरित परिस्थितियों में अन्य यूनियनों की अड़गेबाजी के बावजूद एक शानदार वेतन समझौता
- ★ एन.एफ.टी.ई. द्वारा लगभग गवांए जा चुके प्रमोशन की प्राप्ति
- ★ सभी के लिए लाभप्रद प्रमोशन पॉलिसी (NEPP)
- ★ वी.आर.एस. -सी.आर.एस. की योजना विफल की
- ★ बी.एस.एन.एल. के भवनों व नेटवर्क पर निजी कम्पनियों की कब्जा करने की योजना विफल की
- ★ कर्मचारी हित की असंख्य सुविधाओं के आदेश
- ★ एस.सी./एस.टी. साथियों को प्रदत्त संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा हेतु निरन्तर सफल प्रयास

11 गौरवशाली
वर्ष उपलब्धियों के

हमारे लक्ष्य

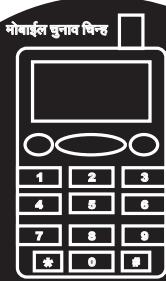
- ★ बी.एस.एन.एल. की रक्षा जोकि सबसे अहम है
- ★ बी.एस.एन.एल. की वित्तीय जीवंतता की सुनिश्चितता
- ★ पर्याप्त उपकरणों की निरंतर आपूर्ति
- ★ वी.आर.एस.-सी.आर.एस. के खिलाफ सतत् संघर्ष
- ★ एस.सी.-एस.टी. कर्मियों को आरक्षण लाभ की सुनिश्चितता
- ★ 78.2% आई.डी.ए. आधार पर सभी लाभ भत्तों की बहाली
- ★ विनिवेश-निजीकरण के खिलाफ सतत् संघर्ष
- ★ प्रमोशन पॉलिसी में समय समय पर कर्मचारी हितों के अनुरूप संशोधन
- ★ स्टेगेनेशन का निराकरण
- ★ बोनस फार्मूले में पुनः परिवर्तन
- ★ बीएसएनएल एमटीएनएल विलय पर रोक
- ★ टॉवर कंपनी का पुरजोर विरोध एवं रोक
- ★ दिवंगत कर्मियों के आश्रितों की नियुक्ति में निरंतरता एवं परिवर्तन हेतु प्रयास
- ★ कैज्युअल-कान्ट्रैक्ट वर्कर्स के मुद्दों का निराकरण
- ★ हमें प्राप्त अधिकारों/वेतन व अन्य लाभ की निरंतरता की सुनिश्चितता
- ★ 1.1.2017 से वेतन पुनरीक्षण आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप लाभ

9

मतपत्र में क्रमांक

एकता के लिए संघर्ष, संघर्ष के लिए एकता

बीएसएनएलईयू गुजारिश करती है
आपके स्नेह की, आपके विश्वास की !



पर मोहर लगाए यह निवेदन...